खण्ड-07 सत्र-05 / अंक-61

बृहस्पतिवार 29 फरवरी, 2024 / 10 फाल्गुन, 1945 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

सातवीं विधान सभा

पाँचवां सत्र

अधिकृत विवरण

(खण्ड-07 सत्र-05 में अंक 50 से अंक 70 तक सम्मिलित हैं)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

राज कुमार

सचिव

RAJ KUMAR

Secretary

महेन्द्र गुप्ता

उप-सचिव (सम्पादन)

MAHENDRA GUPTA

Deputy Secretary (Editing)

विषय सूची

सत्र-5 बृहस्पतिवार, 29 फरवरी, 2024/10 फाल्गुन, 1945 (शक) अंक-61

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1-2
2.	ध्यानाकर्षण एवं निंदा प्रस्ताव तथा उस पर चर्चा	3-35
3.	विशेष उल्लेख (नियम-280)	36-50
4.	ध्यानाकर्षण (नियम-54)	51-87

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-5 बृहस्पतिवार, 29 फरवरी, 2024/10 फाल्गुन, 1945 (शक) अंक-61

दिल्ली विधान सभा

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए:

1. श्री अखिलेशपति त्रिपाठी
2. श्री अजय दत्त
3. श्री अब्दुल रहमान
4. सुश्री भावना गौड
5. श्री बी. एस. जून
6. श्री गिरीश सोनी
7. श्री हाजी युनूस
8. श्री जरनैल सिंह
9. श्री नरेश यादव
10. श्रीमती प्रीति जितेंद्र तोमर
11. श्रीमती प्रमिला धीरज टोकस
12. श्री राजेश गुप्ता
13. श्रीमती राजकुमारी ढिल्लों
14. श्री राजेश ऋषि
15. श्री रोहित कुमार
16. श्री संजीव झा
17. श्री सोमदत्त
18. श्री शिवचरण गोयल
19. श्री एस. के. बग्गा
20. श्री विनय मिश्रा

21. श्री वीरेंद्र सिंह कादियान
22. श्री महेंद्र गोयल
23. श्री मुकेश अहलावत
24. श्री मदन लाल
25. श्री पवन शर्मा
26. श्री प्रलाद सिंह साहनी
27. श्री राजेन्द्र पाल गौतम
28. श्री सुरेंद्र कुमार

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-5	बृहस्पतिवार, 29 फरवरी, 2024/10 फाल्गुन, 1945 (शक)	अंक-61

दिल्ली विधान सभा

सदन 11.18 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

माननीय अध्यक्षः सभी माननीय सदस्यों का स्वागत है, 280 ।

श्री संजीव झाः अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही गंभीर विषय में आपका ध्यानाकर्षण चाहता हूं और 2 मिनट का मैं आपसे टाइम चाहता हूं फिर 280 करा लीजिएगा।

माननीय अध्यक्षः विषय क्या है मतलब ध्यानाकर्षण किस नियम में ध्यानाकर्षण क्या है।

श्री संजीव झाः विषय अध्यक्ष महोदय एक हम निंदा प्रस्ताव लाना चाहते हैं। कल एलजी साहब की चिट्ठी एलजी साहब ने खुद राजनिवास में उसको ट्वीट किया है और वो चिट्ठी की एक कापी हाउस के पास भी है। मैं आपको ये चिट्ठी की कापी मैं भी टेबल पर रख देता हूं और आपक पास शायद आया भी है। एक तो इस चिट्ठी का नेचर पॉलिटिकल है। ये चिट्ठी एक दिल्ली के उप-राज्यपाल लिखेंगे

ऐसी उम्मीद उनसे नहीं थी लेकिन 2-3 बहुत सीरियस कंसंर्न हैं जो इस चिट्ठी में उन्होंने मेंशन किया जो आपकी चेयर को भी demean कर रहा है। उन्होंने ये लिखा है कि CM should advice… I advise you to convey the same to the Hon'ble Speaker of the Assembly and the same should be expunged from the proceedings of the House. एक बात बताईये अध्यक्ष महोदय कोई भी एग्जीक्यूटिव इस हाउस के सुप्रीम को एडवाइज या डायरेक्ट नहीं कर सकता है। अगर उप-राज्यपाल महोदय को इतनी बेसिक बात समझ में नहीं आती है और ये कोई पहली बार नहीं है इस तरह की un-constitutional चिट्ठियां इस हाउस में वो बार-बार लिखते रहे हैं। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि एलजी साहब को हमने पहले भी कहा है कि देखिये एलजी साहब को हो सकता है कि constitution की समझ नहीं हो, हो सकता है कि legislative process की समझ नहीं हो, वो अपाइंटेड आदमी हैं कोई एग्जाम देकर तो वो आए नहीं हैं कि क्वालिफिकेशन उनका चैक हुआ है कि आपका ये क्वालिफिकेशन है, आपको constitution की समझ है, पार्लियामेंट प्रोसेस की समझ है और आप एलजी अपाइंट किये जाते हैं, कोई प्रोसेस... नहीं है। जो भी हजूरेआला को पसंद आया और जो उनकी चाकरी करा वो एलजी बन जाते हैं लेकिन अगर आपको कांस्टीट्यूशन की समझ नहीं है तो आपको एक्सपर्ट रखना चाहिए चूंकि सर दिल्ली की जनता शर्मशार हो रही है। आप जो चिट्ठी लिख रहे हैं इससे ये हाउस और हमारा being a legislature हमारा जो राइट है उसको आप फ्रीज करना चाह रहे हैं और ये कतई ये सदन बर्दाश्त नहीं करेगा।

मुझे ये लगता है कि जिस तरह की लेंग्वेज चिट्ठी में इन्होंने लिखी है एक तरफ ये कहते हैं कि हाउस का जो आपने किया है Delhi Legislative Assembly … surprisingly the Delhi Assembly passeda resolution, the BJP exercise direct control over the Hon'ble LG, on 19th February 2024 तो आपके तो ये देखिये वो क्राइम में कहता है न circumstantial evidence तो ये जो circumstantial evidence है ये दर्शाता है कि वो एलजी बीजेपी कंट्रोल्ड हैं। यह चिट्ठी ही दर्शा रहा है, ये चिट्ठी दर्शा रहा है कि आप दिल्ली के Lt. Governor इस NCT of Delhi Government के आप हैड नहीं हैं, xxxxxxx[1] जो बिधूड़ी साहब को चिट्ठी लिखकर बोलना चाहिए वो चिट्ठी एलजी साहब लिख रहे हैं ये दर्शा रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी के आदमी बनकर काम कर रहे हैं और ये कोई पहली घटना नहीं है लगातार आप चाहे जितनी भी स्कीम रही हों पहले दवा रोकने वाली घटना जो सीएम साहब ने हाउस में ही बताई थी। जिस तरह से आप जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं उसको रोकने की आप कोशिश कर रहे हैं तो ये सारी कोशिश जो है और सारे आपके जो प्रयास हैं ये जितने आफिसर हैं ये आफिसर पहले भी थे ये आफिसर आज भी हैं लेकिन पहले जो काम कर रहे थे आपके आने के बाद वो सारी स्कीम्स जो उन्होंने पहले कराई थी उसको आप रोक रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं, किसके कहने पर रोक रहे हैं और आप क्यों कह रहे हैं। आप इसलिए कर रहे हैं न चूंकि बीजेपी नहीं चाहती है कि ये सारे वेलफेयर का काम दिल्ली की

---

[1] चिन्हित अंश अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदन की कार्यवाही से निकाले गए।

जनता का हो और इसलिए भारतीय जनता पार्टी आपको डायरेक्ट कर रही है और आप अधिकारियों को डायरेक्ट कर रहे हैं। तो मेरा दो सीरियस कंसर्न है एक तो मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल मिनिस्टरसे मैं इस पर रिप्लाई चाहूंगा कि जिस तरह का एलीगेशन इन्होंने लगाया है इसमें क्या सत्यता है हाउस को विस्तार से बताएं और दूसरी बात की इस तरह से हाउस को सुपरसीड करने की कोशिश दिल्ली के एलजी विनय सक्सैना जी न करें। ये एलजी पद की गरिमा को भी ठेस पहुंचा रहे हैं और इस हाउस की जो सेंक्टिटी है उस सेंक्टिटी में इंटरवीन कर रहे हैं मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं।

श्री राजेन्द्र पाल गौतमः माननीय अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः भई एक सेकेंड राजेन्द्र जी।

श्री राजेन्द्र पाल गौतमः दो मिनट दीजिए।

माननीय अध्यक्षः नहीं एक सेकेंड इजाजत लेकर बोलो न, इजाजत तो लेकर बोलें।

....व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः राजेन्द्र जी, मैं सिर्फ इतनी प्रार्थना कर रहा हूं।

....व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः चलिए बोलिए।

श्री राजेन्द्र पाल गौतमः माननीय अध्यक्ष जी, ये जो चिट्ठी एलजी साहब ने लिखी है इस चिट्ठी में ये कह रहे हैं कि 28.02.24 को इन्होंने चिट्ठी लिखी है और कह रहे हैं 19.02.24 को जो रिजोल्यूशन पास हुआ है वो रिजोल्युशन बिलकुल गलत है और वो शब्द हटाये जाने चाहिए जो उन पर आरोप हैं वो गलत हैं। और वो तो यहां तक कह गये कि यूडी डिपार्टमेंट, दिल्ली जलबोर्ड और फाइनेंस डिपार्टमेंट ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हैं ये दिल्ली सरकार के हैं। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हैं दिल्ली सरकार के हैं तो फिर जब मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी लिखी, हमारे मंत्रीगण ने चिट्ठी लिखी की आप वाटर पालिसी वन टाइम जो सेटलमेंट स्कीम जलबार्ड ने अप्रूव कर दी है आप उस पर कैबिनेट नोट बनाकर दीजिए चूंकि ये बात सदन के अंदर खुद मंत्री जी ने बताई है कि कैबिनेट नोट लिखने के लिए बोला उन्होंने फाइल पर उसको लिखकर मना कर दिया कि हम नहीं बनाएंगे। तो अगर ये हमारे अधीन है और मुख्यमंत्री कह रहे हैं ये हमारे कहने पर काम नहीं कर रहे आप इनके खिलाफ कार्यवाही कीजिए इनको सस्पेंड कीजिए उसके बाद एलजी साहब अगर उनको बचाने में लग गये। उनके खिलाफ कोई भी कार्यवाही आज तक जितनी कार्यवाही करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने या मंत्रीगण ने जो भी अधिकारी दिल्ली सरकार के कहने पर काम नहीं कर रहा है और वो भी लीगल काम जायज काम जो करने की उसकी कानूनी जिम्मेदारी बनती है। उसके बारे में जितना भी आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने और मंत्रीगण ने चिट्ठियां लिखकर कार्यवाही करने के लिए निवेदन किया है उस पर एक पर भी कार्यवाही आज तक एक

भी बता दीजिए एक पर भी कार्यवाही एलजी साहब ने की हो तो। एलजी साहब इसमें कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये जो एक सरकार जो दिल्ली के एमएलए और मंत्रीगण हैं they are planning petty political games वो पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं। पॉलिटिकल गेम हम खेल रहे हैं, हमारी सरकार खेल रही है या आप खेल रहे हैं। आप उनके बिहाफ पर कर रहे हैं सब कुछ आप करवा रहे हैं उनसे। अगर आप नहीं करवा रहे तो फिर इन अधिकारियों पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई। जब दिल्ली जलबोर्ड ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को पास कर दिया, बोर्ड ने पास करने के बाद इन अधिकारियों को कहा कैबिनेट में नोट तैयार कीजिए कैबिनेट के लिए यूडी अधिकारियों ने मना कर दिया, वाटर के सीईओ ने मना कर दिया। तो ये अधिकारी अगर काम नहीं कर रहे सरकार के कहने के बाद भी तो वो कार्यवाही करने के लिए जो मुख्यमंत्री उनसे कह रहे हैं तो कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्षः चलिए अब कंकलूड करिये।

श्री राजेन्द्र पाल गौतमः तो इस तरह का आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा ये मिसलीडिंग स्टेटमेंट बता रहे हैं। मिसलीडिंग नहीं है, ये तो पूरी दिल्ली देख रही है सब लोग देख रहे हैं कौन मिसलीड कर रहा है कौन पॉलिटिक्स कर रहा है किसके इशारे पर पॉलिटिक्स हो रही है। ये पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर दिल्ली सरकार को पूरी तरह से ध्वस्त करने की एक साजिश है और ये सदन इसको किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकता। हम इनके इस लैटर की

जो चिट्ठी इन्होंने लिखी है मुख्यमंत्री जी को जिस तरह के आरोप लगाकर हम उसकी भर्त्सना करते हैं।

माननीय अध्यक्षः मदनलाल जी।

श्री मदनलालः अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं सदन का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया 19 तारीख को और उस रेजोल्यूशन में एक सबसे बड़ा तथ्य था कि दिल्ली के लगभग साढ़े दस लाख से ज्यादा लोगों को जो बिल भेजे गये हैं वो इनकरेक्ट हैं, गलत हैं, लोगों को उससे परेशानी है। दिल्ली के लोग बहुत ईमानदार हैं और ईमानदारी से वो पैसा देना चाहते हैं। उनमें से 27 लाख में से लगभग 40 परसेंट यानी साढ़े दस लाख से ज्यादा लोगों को ये शिकायत है कि उनके बिल बढ़े हुए भेजे गये हैं। ये इसलिए भी बात समझ में आती है कि कोरोना के समय में जब लोग अपने घरों में दुबके हुए थे बाहर नहीं निकल रहे थे तब दिल्ली जलबोर्ड के अधिकारी जो मीटर रीडिंग के लिए तैनात थे वो सही तरीके से रीडिंग नहीं कर पा रहे थे और यही कारण था कि उन्होंने ऐवरेज के नाम पर अनाप-शनाप लोगों को बिल भेजे लोगों ने उस बिल को नहीं पे किया। इससे एक बड़ा नुकसान यह रहा कि सरकार को पैसा जितना जेनुअनली आना था वो भी नहीं आया और कंज्यूमर हमेशा इस खतरे में जूझता रहा कि उसको बढ़े हुए बिल देने पड़ेंगे या उसका पानी का कनेक्शन कट जाएगा। माननीय केजरीवाल जी की नजर में आया, मंत्री महोदय बहुत चौकन्ने हैं उन्होंने डिस्कस किया और अंत में सरकार ने निर्णय लिया कि ऐसे साढ़े दस लाख से ज्यादा लोगों के

बिल को ठीक कराने के लिए जो उनके दो बिल पूरे महीने में किसी भी दिन के दो बिल जो वो करेक्ट समझेंगे उनके हिसाब से ऐवरेज मान लिया जाएगा और बिल पे करेंगे। ये किसी को दया या भीख नहीं दी जा रही है सरकार की मंशा है कि लोगों को जो गलत बिल भेजे जा रहे हैं उनको ठीक किया जाए। हमने इसी सदन में देखा कि माननीय उप–राज्यपाल महोदय 15 तारीख को जब सदन पहली बार यहां बैठा तो इस सरकार की भूरि–भूरि प्रशंसा कर रहे थे। उन्होंने जल विभाग की प्रशंसा की और कहा मेरी सरकार और मेरी सरकार कहते हुए उन्होंने कम से कम 20 बार से ज्यादा दिल्ली सरकार के कार्य–कलापों का बखान किया उनकी प्रशंसा की। महोदय, जब ये प्रस्ताव यहां लाया गया और इसको यहां पास किया गया रेजोल्यूशन को तो उससे पहले अगर आप देखें तो लगातार सरकार कोशिश करती रही कि वो अधिकारी जो इसके लिए कंसर्ड हैं जो अब बड़ी सरकार के अंदर काम करते हैं या मैं कहूं एलजी साहब के इशारे पर काम करते हैं। वो लगातार कोशिश करते रहे की ये बिल ठीक न हो जिससे सरकार की बदनामी हो और सरकार को राजस्व न आए। सरकार को राजस्व नहीं आएगा तो प्रोग्रेस के डेवलपमेंट के जितने काम हैं वो रुकेंगे। यही कारण है कि आज दिल्ली जलबोर्ड के बड़े अधिकारियों ने या मैं कहूं जो सीईओ साहब हैं उन्होंने सबसे पहले फैसला लेकर दिल्ली में जितनी भी सीवर लाइनें डालनी हैं उनका काम बंद कर दिया है। पानी की नई लाइनें डालना बंद कर दिया है। जितने दिहाड़ी मजदूर थे वो बंद हो गये हैं उनको सबको उनका कांट्रेक्ट टर्मिनेट कर दिया है। सरकारी नौकरी मिल

नहीं रही है, जो पहले सरकारी नौकरी कर रहे थे सीवर की सफाई का और नल की मेनटेनेंस का वो अधिकारी ज्यादातर रिटायर हो गये हैं। ऐसे में दिल्ली इस समय एक ऐसे कगार पर पहुंच कई है कि लोग इससे बहुत ज्यादा परेशान हैं चाहे वो सीवर की हो या पानी की हो। इससे दोनों को नुकसान है कंज्यूमर परेशान है सरकार को रेवेन्यू नहीं आ रहा है। और अब जब ये रेजोल्यूशन पास हुआ है तो अध्यक्ष महोदय एलजी साहब को परेशानी हो गई है और उन्होंने उस चिट्ठी में क्या लिखा है उन्होंने लिखा है कि LG writes open letter to CM, Kejriwal says: 'water, finance, UD departments totally under your control, I have nothing to do with it. Take decisions, do not blame other, benefit all 27 lakhs consumers, why only 10 lakhs. Return the bills paid by 17 lakh honest consumers with interest, LG.' सर जब ये इस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये ऐसा है जैसे ये देशद्रोह की बात कर रहे हैं। ये सब कह रहे हैं, कोई सबको पैसे नहीं देने हैं। तो सरकार की तो जो स्कीम है वो केवल 20 हजार लीटर की है। ये तो जिन लोगों ने 20 हजार लीटर से ज्यादा इस्तेमाल किया है वो कह रहे हैं उनके भी पैसे वापस करो। ये किस तरह के एलजी हैं, ये किसके इशारे पर काम कर रहे हैं और चुना किसने है। जो काम माननीय लीडर आफ अपोजिशन श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी साहब को करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके सारे साथी जो उनके साथ खड़े होते थे वो सारे उन्हीं एलजी महोदय की अवमानना के केस में इस सदन से बाहर कर दिये गये हैं। ऐसे में एलजी साहब का ये ब्लेम करना।

माननीय अध्यक्षः कंकल्यूड करिये मदनलाल जी कंकल्यूड करिये।

श्री मदनलालः ये ऐसे में एलजी साहब का इस हाउस को ब्लेम करना और सबसे बड़ा आपको ब्लेम करना कि आपके यहां से जो रेजोल्यूशन पास हुआ है वो बहुत गलत है। मुझे लगता है कि दो करोड़ जनता के द्वारा चुने हुए इन लोगों को जो जनता के फायदे की बात कर रहे हैं इलेक्टेड लोगों को एक सिलेक्टेड अर्थॉरिटी चैलेंज कर रही है वो सलाह दे रही हैं कि सबके माफ कर दो, सबके पैसे वापस, माफ भी करो सबके पैसे वापस करो। ऐसे है जैसे ये पानी का कोई बंटवारा हो रहा है। ये कैसे एलजी हैं, इससे पहले हमने देखा जितने एलजी महोदय दिल्ली में आए।

माननीय अध्यक्षः मदनलाल जी कंकल्यूड करिये समय हो रहा है।

श्री मदनलालः वो सरकार के काम को रोकने की कोशिश तो करते थे पर सभ्य तरीके से। जिस तरीके से एलजी महोदय बर्ताव कर रहे हैं ऐसा लगता है कि वो एक पैरलल सरकार चला रहे हैं। हमने यहां देखा है बहुत सारे मेंबर्स को वो हर बार यहां एक मुद्‌दा उठाते हैं के सर मुझे पता नहीं जो सब्जेक्ट हमारे हैं उन्हीं में एलजी महोदय वहां जाकर विजिट कर रहे हैं आदेश दे रहे हैं, तो चुने हुए लोग क्या करेंगे? चुने हुए लोगों को क्या करना है, वो लोगों को रिप्रजेंट कर रहे हैं, वो लोगों की भावनाएं समझते हैं, वो लोगों की दिक्कतों को समझते हैं, वो लोगों की दिक्कतों का निदान करना चाहते हैं, पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते। तो जिस तरह का ये लैटर है ये बहुत गलत भाषा का

इस्तेमाल हुआ है। मैं संजीव जी के निंदा प्रस्ताव का पूरा समर्थन करता हूं और मुझे लगता है हाउस मेरी बात से सहमत होगा और संजीव जी की बात से सहमत होगा। हमें एक निंदा प्रस्ताव जरूर उनको भेजना चाहिए जिससे उनको महसूस हो कि वो अपनी हदें पार कर रहे हैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः बिधूड़ी जी दो मिनट।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के माननीय उप-राज्यपाल महोदय हमारे गार्जियन हैं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः भई अजय दत्त जी ऐसे काम नहीं चलेगा प्लीज मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः हैड आफ द स्टेट हैं और समय-समय पर दिल्ली के ऑनरेबल एलजी दिल्ली की इलेक्टेड गवर्नमेंट को एडवाइज दे सकते हैं। उस एडवाइज को मानना या न मानना वह सरकार के ऊपर निर्भर करता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं दिल्ली के माननीय उप-राज्यपाल महोदय को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक क्लेरिफिकेशन दिया है कि चाहे जलबोर्ड हो एक अटोनोमस बॉडी है उसके ऊपर पूरा अधिकार दिल्ली सरकार का है। फाइनेंस हो, अर्बन डिपार्टमेंट हो यह ट्रांसफर सब्जेक्ट है और कोई भी फैसला यदि सरकार इन विभागों में लेना चाहती है तो उनको पूरा अधिकार है। ये दिल्ली के ऑनरेबल एलजी ने कहा है तो हमें इसका स्वागत करना चाहिए और यदि दिल्ली

के ऑनरेबल एलजी यह कह रहे हैं कि 10 लाख लोगों के जो बिल गलत आ गये ये तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने भी कहा है कि भई जो बिल भेजे गये हैं उसमें कहीं न कहीं गलती हुई है उसको सुधारने की आवश्यकता है। तो इसके विरोध में कौन है, नहीं मैं कहता हूं इसके विरोध में कौन है और मैं हाउस में जब कोई बात कही जाए तो पुख्ता सबूत के साथ बात की जाए और यदि दिल्ली के ऑनरेबल एलजी ने अगर कहीं फाइल पर कोई ऐसी नोटिंग है कि दिल्ली सरकार के इस जो मूव दिल्ली सरकार का है दिल्ली सरकार ने ये जो मामला आगे बढ़ाया है अगर कहीं एक नोटिंग इस हाउस में आपको जरूर दिखानी चाहिए कि दिल्ली के ऑनरेबल एलजी इस स्कीम में रुकावट डाल रहे हैं और यदि सरकार के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है तो मैं ये समझता हूं कि इस हाउस में जो एलजी के ऊपर आरोप लगाये जा रहे हैं, जो लोग लगा रहे हैं उनको दिल्ली के ऑनरेबल एलजी से माफी मांगनी चाहिए मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्षः चलिए बिधूड़ी जी।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः तो आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं कहता हूं गंभीरता के साथ चर्चा होनी चाहिए हम खुलकर चर्चा करेंगे।

माननीय अध्यक्षः बैठिये, माननीय मंत्री जी सौरभ जी।

श्री राजेन्द्र पाल गौतमः माननीय अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः भई, अब इस पर लम्बा।

श्री राजेन्द्र पाल गौतमः सिर्फ एक चीज चाहता हूं, अध्यक्ष जी, सिर्फ एक चीज चाहता हूं।

माननीय अध्यक्षः भई, आपको समय मिल चुका है।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः वो सौरभ जी को बोलने दो ना जी। सौरभ जी को बोलने दीजिए, वो बताएंगे।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः भई, बिधूड़ी जी, प्लीज।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः श्रीमान सौरभ जी, माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे चर्चा का।

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष जी एक चर्चा बुराड़ी से हमारे विधायक श्री संजीव झा जी ने शुरु की। मैंने ये चिट्ठी एलजी साहब की मंगवाई अभी। मुझे नहीं पता ये एलजी साहब ने चिट्ठी किससे लिखवाई है क्योंकि उन्होंने नहीं लिखी है मैं ये समझ सकता हूं उनकी इतनी अंग्रेजी है ही नहीं कि वो ऐसी चिट्ठी लिखें, मैं उनसे कई बार बातचीत कर चुका हूं जिससे आपको पता चल जाता है किस आदमी की कैसी भाषा हो सकती है। ये चिट्ठी जिसने भी लिखी है बेहद भद्दी चिट्ठी है और घटिया भाषा का प्रयोग किया है और राजनीतिक चिट्ठी लिखी है और राजनीतिक चिट्ठी लिखते समय एलजी साहब ने

कहा कि मुझ पर राजनीति करने का इल्जाम लगाया गया है और जो अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल किये हैं वो हैं मुझे कहा गया है कि 'BJP exercises direct control over Hon'ble LG.' उन्होंने इस चीज पर ऐतराज जताया है और उन्होंने लिखा है ये जो स्टेटमेंट है गलत है unacceptable है irresponsible है and it not only breaches all propriety and constitutional provisions but is also affront to the constitutional office of LG for petty political games.' मैं हैरान हूं खुद एक राजनीतिक चिट्ठी लिखते समय एलजी साहब की तरफ से ये दुहाई दी गई है कि इस चिट्ठी में एक constitutional मर्यादा और प्रोपराइटी को जो है आघात पहुंचाया है। ये चिट्ठी किसी से भी आप पढ़वा लीजिए ये चिट्ठी एलजी ऑफिस जिसको एक sacrosanct ऑफिस माना जाता है, उस sacrosanct ऑफिस पर एक धब्बा है ये चिट्ठी। अब मैं आता हूं राजनीति के ऊपर। अध्यक्ष जी मैं राजनीतिक आदमी हूं, मुख्यमंत्री राजनीतिक आदमी हैं, रामवीर सिंह बिधूड़ी राजनीतिक आदमी हैं, ये ऐसी चिट्ठी मुझे लिखें, मंजूर है। ये ऐसी चिट्ठी मुख्यमंत्री को लिखे मंजूर है, मगर एलजी इस तरीके की चिट्ठी लिखें ये हमारे संविधान में मंजूर नहीं है। अब एलजी ने अपने आपको constitutional बताया। रामवीर बिधूड़ी जी एक उदाहरण कह रहे थे कि एक सबूत रखो, मैं एक सबूत रखता हूं और बिधूड़ी जी के सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि बिधूड़ी जी इस सबूत को समझ सकते हैं क्योंकि राजनीतिक आदमी हैं, एलजी के जो लोग सुन रहे हों, वो उनको बता दें सौरभ भारद्वाज आज सबूत रख रहा है इस हाउस के सामने, अगर उनमें दम

है तो इस सबूत के खिलाफ बताएं कि मैं गलत बोल रहा हूं। अध्यक्ष जी, देश का संविधान कहता है 10 एल्डरमैन सरकार लगाएगी, हमें नहीं लगाने दिए एलजी साहब ने लगाए, जबरदस्ती लगाए, चलिए ठीक है। वो कौन लोग थे, वो भारतीय जनता पार्टी के छोटे-छोटे कार्यकर्ता थे। वो एलजी साहब को वो कहां मिल गए, कहां से आई वो लिस्ट। कोई नरेला के अंदर छोटा सा कार्यकर्ता है, कोई अलीपुर गांव में है, कोई बुद्धविहार में है, कोई विलेज दरियापुर के अंदर है, कोई मेरे ईस्ट ऑफ कैलाश के अंदर है। ये छोटे-छोटे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने ही तो दी होगी, ये एलजी साहब के रिश्तेदार हैं तो एलजी साहब बता दें कि भई ये आदमी मैं इसको ऐसे जानता हूं, इसको मैं ऐसे जानता हूं, इसको मैं ऐसे जानता हूं और ये सारे के सारे एमसीडी के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर दक्ष हैं। तो आपने अपना जो पहला काम दिल्ली में आकर किया एमसीडी के अंदर वो आपने प्योरली राजनीति की है और दूसरा उदाहरण मैं उनका देता हूं, सबूत है उनका। उन्होंने उस-उस जोन के अंदर ये एल्डरमैन दिए जिस-जिस जोन के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जरूरत थी, जैसे नरेला में दिए, सिविल लाइंस में दिए और सैंट्रल जोन में दिए और गिनती भी उतनी ही दी। नरेला में 4 दिए, सिविल लाइंस में 4 दिये, सैंट्रल जोन में 2 दिए, वाह भई वाह। आप क्या बेवकूफ समझते हो सबको, मैं सबूत दे रहा हूं। ये सबूत है कि एलजी जो हैं प्योरली राजनीतिक आदमी है, उनका कोई लेना-देना नहीं है constitutional propriety से और इससे अब इनकी चिट्ठी के ऊपर आता हूं मैं। इन्होंने

लिखा 'water scheme which does not exist on paper' ये सरासर जो है एलजी साहब ने गलत बात कही। ये वॉटर स्कीम बाकायदा पेपर पर है, बाकायदा दिल्ली जल बोर्ड ने अपनी 13 जनू, 2023 की बोर्ड मीटिंग के अंदर इस स्कीम को पास किया है। दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से बार–बार ये कहा जा रहा था, क्योंकि अफसर जो हैं वो इस स्कीम से अनकम्फर्टेबल थे और कारण ये था कि उनके ऊपर, ऊपर से जो है एलजी साहब का और उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का दबाव था, ये सबको मालूम है। अफसर नहीं चाहते ये स्कीम आए, वो क्यों नहीं चाहते, क्योंकि एलजी साहब नहीं चाहते, वो क्यों नहीं चाहते क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती। इसलिए अफसर बार–बार ये कहते रहे कि साहब हम ना इस स्कीम के अंदर मोडिफिकेशन करना चाहते हैं। मोडिफिकेशन करना चाहते हैं, हम रूके रहे। मैंने खुद फाइल पर लिखा, मैं जब यूडी मिनिस्टर बना, आतिशी चेयरपर्सन थी, पहले मैं ही चेयरपर्सन था, मैं ही यूडी मिनिस्टर था। तो जब आतिशी चेयरपर्सन बनी तो मैंने खुद अपनी कलम से फाइल पर लिखा हुआ है, अपनी हैंडराइटिंग में, की भई मुझे कहा गया है कि जल बोर्ड जो है इस स्कीम को जो है दुबारा से देख रहा है, लिहाजा ये फाइल वापस करता हूं। हमने वापस की जल बोर्ड को फाइल। मगर जब 6 महीने बीत गए, जून के अंदर स्कीम पास हो रखी है, दिसम्बर बीत गया तो हमें ये बात समझ में आ गई कि जल बोर्ड कोई नई स्कीम नहीं लाना चाहता सिर्फ पुरानी स्कीम ना आए इसलिए नई स्कीम का बहाना कर रखा है कि हम कुछ और कर रहे हैं, हम कुछ और कर रहे हैं। तो

आतिशी जी से लिखित में हमने पूछा एज ए यूडी मिनिस्टर मैंने उनसे पूछा की भई आप बताइये, बार–बार कहा जा रहा है कोई नई स्कीम आ रही है तो उन्होंने लिखित में दिया है अध्यक्ष जी मुझे नोटिंग है फाइल के ऊपर की हमारे यहां पिछले एक महीने से ये चर्चा हो रही है कि कोई नई स्कीम लेकर आएंगे, कोई मोडिफिकेशन करेंगे इस स्कीम में, 13 जून, 2023 वाली स्कीम में कोई मोडिफिकेशन करेंगे। मगर कोई मोडिफिकेशन नहीं हो पा रही है, समय बीतता जा रहा है लिहाजा इसी स्कीम को जो बोर्ड से पास हुई है, उसको ही फाइनल स्कीम माना जाए और इसको कैबिनेट में भेजा जाए। ये तो जाहिर सी बात है, ये तो बड़ी साधारण सी बात है अध्यक्ष जी कि अगर कोई स्कीम पास हुई है और उस स्कीम को बदलने की चर्चा हो रही है, मगर कोई बदलाव पास नहीं हो रहा है तो जो स्कीम पास हो रखी है वही फाइनल है और जब दिल्ली जल बोर्ड की चेयरपर्सन ने ही लिखकर दे दिया कि यही फाइनल है, तो वो हम मानेंगे की वो फाइनल है और वो फाइनल स्कीम हमने जो है कैबिनेट के लिए जो यूडी सेक्रेटरी साहब को भेज दी कि यूडी सेक्रेटरी जो है जो एसीएस है वो इस स्कीम को जो है लेकर आएं। अब हर स्कीम को रोकने का एक ही तरीका है कि आप उसको जो है फाइनेंस के पास भेज दें, फाइनेंस उसपर या तो कमेंट दे ही ना, दे तो ऐसे उलजल्लुल बातें उसपर लिख दें कि वो स्कीम आ ना सके, वो ही फाइनेंस जो है फिलहाल कर रहा है। जिस दिन एलजी साहब का यहां पर अभिभाषण था मुझे लग रहा है 15 फरवरी थी। 15 फरवरी को मैं था, एलजी

साहब थे, मुख्यमंत्री जी थे, हमारी आतिशी थी और by the way उस वक्त राखी बिड़ला भी सामने बैठी हुई थी, सर आप भी थे मुझे लगता है, मगर आपको इन्वोलव करना ठीक नहीं है। आप भी थे वहां पर और वहां पर चर्चा हुई एलजी साहब के सामने और एलजी साहब ने कहा नहीं–नहीं आप एक काम कीजिए आप सीएस को लिखिए मैं भी सीएस को कहूंगा इस स्कीम को लाया जाए। अरे जब सीएम, जब खुद एलजी साहब से चर्चा हुई इस स्कीम के बारे में तो एलजी साहब कैसे कह रहे हैं कि इस स्कीम के बारे में, ये कोई स्कीम ही नहीं है, पेपर पर ही स्कीम नहीं है, ये तो सरासर गलत बात है, ये तो सबके सामने है और आप ही को चिट्ठी लिख रहे हैं कि ऐसी कोई स्कीम नहीं है। जबकि सामने चर्चा हुई है एलजी साहब के साथ। ये जो है इस तरीके की जो छोटी–छोटी चीजें हैं अध्यक्ष जी वो इतने बड़े constitutional जो ऑफिस हैं एलजी साहब का उसको जो है ये छोटा करती हैं, एलजी साहब को इस बात को समझना चाहिए आज वो एलजी हैं कल कोई और एलजी आएगा, उससे पहले भी एलजी आए हैं। मगर उनको उस ऑफिस की मर्यादा रखनी चाहिए। अब अगला उन्होंने क्या लिखा की ये transferred subject है, यूडी, जल बोर्ड और फाइनेंस डिपार्टमेंट इसका पूरा जो है कंट्रोल वो क्योंकि चुनी हुई सरकार के पास है तो इसमें मेरे को क्या लेना–देना वाह भई वाह। अभी तक क्या हमें यही समझ में नहीं आया कि कंट्रोल किसके पास है। अगर कंट्रोल हमारे पास ही था और हमारे पास ही रखना था तो केंद्र सरकार क्यों जो है नया एक्ट लेकर आई थी, अमेंडमेंट लेकर आई थी 2023 के अंदर। वो

कंट्रोल का ही तो झगड़ा था कि सब्जैक्ट हमारे पास रहें मगर कंट्रोल एलजी साहब का और भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र का रहे, वो आपने कंट्रोल ले लिया और वो कंट्रोल एलजी साहब, एलजी साहब दोनों तरीके की बातें करते हैं, मैं हैरान हूं। जब कोई मामला ंस जाता है, तो वो चिट्ठी पर लिखते हैं ये तो ट्रांस्फरड सब्जैक्ट है ये तो आपके अंडर है। अब मैं एलजी साहब का ही ट्विटर हैंडल देखकर आपको बता रहा हूं अध्यक्ष जी। दो दिन पहले का ट्विट है उनका, मैं आपको दिखा देता हूं एलजी साहब का। एलजी साहब का पांच दिन पुराना ट्विट है 'I visited the historical commercial hubs of Kashmere Gate, Saint James Church complex, Kamla Market at Ajmeri Gate and travelled through Shardhanand Marg to तीस हजारी' अखबार के अंदर इनकी प्रेस रिलीज आई है कि मैंने ये डायरेक्शन दी इस बाजार को ठीक कर दो, इस बाजार को ठीक कर दो, इस बाजार को ठीक कर दो, ये बाजार आपके पास कहां से आ गए, ये तो ट्रांस्फरड सब्जैक्ट है। या तो वो पीडब्ल्यूडी के हैं, या वो कुछ सड़कें एमसीडी की हैं, आपका क्या लेना-देना उसके अंदर और आपके साथ दिल्ली सरकार के सारे अधिकारी दिख रहे हैं इस ोटो में। ये एमसीडी के कमिश्नर है, ये भी ट्रांस्फर्ड सब्जैक्ट हैं आप क्यों लेकर घूम रहे हो इनको। तो भई आप ये क्या लिखते हो कि आप चिट्ठी में कुछ लिखते हो, अखबारों में प्रेस रिलीज कुछ और देते हो, ऐसे कोई ना चलेगा। उससे पहले हमारे बुराड़ी के विधायक यहां पर हाउस में हैं और एलजी साहब जो है वो बुराड़ी में घुम रहे हैं, सीवर की बात कर रहे

हैं, नालियों की बात कर रहे हैं। सीवर क्या ट्रांस्फर्ड सब्जैक्ट नहीं है, नालियां क्या ट्रांस्फर्ड सब्जैक्ट नहीं है, सड़कें क्या ट्रांस्फर्ड सब्जैक्ट नहीं है? आप सारे के सारे अफसरों को वहां पर लेकर गए, सारे ट्रांस्फर्ड सबजैक्ट के अफसर थे, इरीगेसन फलड कंट्रोल का अफसर आपके साथ, पीडब्ल्यूडी का अफसर आपके साथ, जल बोर्ड का अफसर आपके साथ, एमसीडी का अफसर आपके साथ। आप उनको डायरेक्शन दे रहे हो, अगले दिन अखबार में छपवा रहे हो और अब कह रहे हो कि ये ट्रांस्फर्ड सब्जैक्ट हैं। भई ट्रांस्फर्ड सब्जैक्ट हैं तो आप क्यों ले जा रहे हो, ट्रांस्फर्ड सब्जैक्ट के अफसरों को, आप कैसे प्रेस रिलीज दे रहे हो उसके बारे में? आप खुल्लमखुल्ला झूठ बोल रहे हो और बात कर रहे हो प्रोपराइटी की, ये गलत है। उससे पहले किराड़ी में गए, किराड़ी में क्या करने गए आप? किराड़ी के अंदर भी वो ही सीवर की बात, पानी की बात, गलियों की बात ये सारे ट्रांस्फर्ड सब्जैक्ट हैं। और अध्यक्ष जी, मूल बात ये है अगर वो आपका ही सब्जैक्ट था तो आप गाली किसको दे रहे हो? तो आपका ही था, आपको ही करना था, हमेशा ही आपका था। अगर आप ये कह रहे हो कि ये नहीं हुआ ये होना चाहिए। इसका मतलब आप यही कह रहे हो ना की चुनी हुई सरकार ने नहीं किया ये होना चाहिए और चुनी हुई सरकार ने नहीं किया इसका मतलब वो ट्रांस्फर्ड सब्जैक्ट है, वो इलैक्टिड गवर्नमेंट का सब्जैक्ट है। आप उसमें क्यों गए, किराड़ी क्यों गए, आप बुराड़ी क्यों गए, आप दिल्ली के पुराने बाजारों में क्यों जा रहे हो और जब बात आती है तो आप कहते हो आपके पास कंट्रोल नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा अध्यक्ष जी। ये झूठ है।

...व्यवधान...

माननीय स्वास्थ्य मंत्री: सब जगह गए, अरे आप विधायकों को बुलाइए।

...व्यवधान...

माननीय स्वास्थ्य मंत्री: अच्छा ये बात भी है। अध्यक्ष जी मैं एक-एक करके चिट्ठी पर आता हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एलजी साहब के दस्तख्त से जो चिट्ठी जिसने भी लिखी है ये गलत है, ये फैक्चुअली गलती है। और इसके बाद अध्यक्ष जी मैं इस पर भी आता हूं।

माननीय अध्यक्ष: साहनी जी प्लीज।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री: इसके बाद ये कहा गया कि जी ये जो हाउस के अंदर रिजोलूशन पास हुआ है वो factually incorrect है, बिल्कुल नहीं है incorrect, बिल्कुल ठीक है। 13 जून, 2023 को ये पोलिसी पास हुई है, ये factually correct है। जनवरी के अदर ये पोलिसी आई पहली बार। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी उस वक्त चैयरमेन हुआ करते थे, मैं उस वक्त वायस चैयरमेन हुआ करता था, ये डिस्कसन हुआ। मगर इस पोलिसी के ऊपर आम राय नहीं बनी तो मनीष जी ने कहा इसको दुबारा देखेंगे। 6 महीने तक हमने उसके ऊपर काम किया, सारा डेटा निकाला। फिर हम इसको 13 जून को लेकर आए और तब ये पोलिसी पास हुई। इसके अंदर जो रेजूलुशन है मुझे याद है गौतम जी ने रखा था वो रेजूलुशन, सोमनाथ जी ने रखा था,

पानी वाला जो रेजूलुशन था। वो जो भी रेजुलूशन था वो फैक्चुअली बिल्कुल करैक्ट है। इसके अंदर कोई दो राय नहीं है और फिर इसके बाद जो एलजी साहब ने एक बात और कही है, बड़ी मजेदार बात है। क्या होता है कि जब आदमी खुद लिखता है तो उसको याद होता है कि मैंने क्या किया और मैं क्या लिख रहा हूं। जब कोई और लिखता है तो उसको याद नहीं रहता। 2022 के अक्टूबर के अंदर एलजी साहब ने ढोल बजाया कि मैं एमसीडी के अंदर amnesty स्कीम ले आया, मैं समृद्धि योजना ले आया। अब एलजी साहब ने ढोल क्यों बजाया अध्यक्ष जी क्योंकि उस वक्त एमसीडी समाप्त हो चुकी थी, नया चुनाव इन्होंने एक साल तक कराया नहीं, इसलिए एमसीडी प्रैक्टिकली एलजी साहब के अंडर थी। तो एलजी साहब ने बकायदा प्रेस काँफ्रेंस की, वो amnesty स्कीम रिलीज की एमसीडी की और उसके अंदर एलजी साहब ने कहा कि भईया जिसने आज तक प्रोपर्टी टैक्स नहीं दिया वो 6 साल का दे दो सारा माफ। एलजी साहब ने कहा। तब नहीं सोचा एलजी साहब ने की जो अभी हमेशा से जो प्रोपर्टी टैक्स देते आ रहे हैं उनका क्या होगा, उनको सबको वापस कर देते तब। यहां पर हम ये कह रहे हैं कि जी 10 लाख का ही क्यों 27 लाख का माफ कर दो। जिन्होंने दे दिया उनका भी माफ कर दो, आपने क्यों नहीं किया तब, तब तो वो स्कीम आप लाए थे। एमनेस्टी स्कीम अध्यक्ष जी हमेशा इसी तरीके से होती है कि जिस-जिस का विवाद बच गया है, जिस-जिस का झगड़ा अभी भी पड़ा हुआ है और उसके अंदर समस्या चल रही है तो उसको कोई स्कीम लाके उसको ठीक किया जाए। ये हर सरकार का

कायदा होता है, सैंटर के अंदर भी ऐसे ही होता है, एलजी साहब ने खुद ऐसा किया और अब वो लिख रहे हैं कि साहब ये ऐसे हो गया। इसके बाद अध्यक्ष जी उन्होंने कई सारी बातें लिखी हैं इसके अंदर वो बिल्कुल पोलिटिकल बातें हैंकि कुछ कालोनियों के अंदर पानी क्यों नहीं पहुंचा, उन्हें पता ही नहीं है, दिल्ली के बारे में, जानकारी ना हो तो यही होता है। भईया कुछ कालोनियाँ ऐसी हैं जो फॉरेस्ट की लैंड पर बनी हुई हैं, कुछ कालोनियाँ ऐसी भी हैं जो एएसआई की लैंड पर बनी हुई हैं। वहां का एनओसी नहीं मिल रहा इसलिए वहां पर पानी की लाइन नहीं डाली जा रही है, वहां केवल इसलिए सीवर की लाइन नहीं डाली जा रही। वहां का एनओसी एलजी साहब दिलवा दें हम अगले दिन से लाइन डाल देंगे। उनको जानकारी ही नहीं है, एलजी साहब को कोई भी दिल्ली के बारे में जानकारी नहीं है और जो आदमी चिट्ठी लिखता है उसको तो कुछ भी जानकारी नहीं है। इसके बाद अध्यक्ष जी इन्होंने यही कह के अपनी बात खत्म की है और एक बात जो उन्होंने बार-बार कही है वो ये कहा है कि जी 2013 के बाद हमने हर एलजी के बारे में बोला कि उन्होंने काम नहीं करने दिया। अध्यक्ष जी ये बात ठीक है कि हमने हर एलजी के बारे में बोला कि उन्होंने काम नहीं करने दिया, मगर इनसे पहले जितने भी एलजी थे मैं मानता हूं कि हमारा हाउस का एक-एक आदमी इसके ऊपर जो है एग्री करेगा। हमारे जितने भी इससे पहले के एलजी थे उनके साथ विवाद ऐसे होता था कि हमें सीसीटीवी लगाना है वो सीसीटीवी नहीं लगाने दे रहे, हमें वाईफाई लगाना है वो हमारे वाईफाई के ऊपर एतराज लगा रहे

हैं। मगर ऐसा कोई एलजी अभी तक नहीं आया था अध्यक्ष जी, 2013 से मैं भी राजनीति के अंदर सक्रिय हूं जिसने अस्पतालों के अंदर दवाईयाँ रूकवा दी हों, ऐसा एलजी नहीं आया था आज तक अध्यक्ष जी। एक दिल्ली का कोई जवान बच्चा अगर रोड के ऊपर एक्सीडेंट होता है उसका खून बहने से मृत्यु हो जाती है कई बार देखा, कई बार ये देखा कि अस्पताल सरकारी ले जाने के चक्कर में पुलिस 30–30 किलोमीटर जो है ले जाती है निर्भया के मामले में भी यही बताया जाता है कि अस्पताल इतना दूर था सरकारी कि उसको ले जाने के समय में इतना ब्लड लॉस हो गया की वो निर्भया जो है वो नहीं बच पाई बाद में। और अकसर ये कहा जाता है कि जो एक्सीडेंट होता है उसमें एक घंटे के अंदर अगर आप उसको अस्पताल पहुंचा दो तो वो गोल्डन आवर होता है, वर्ना उसकी बचने की जो है गुंजाइश कम हो जाती है इसके लिए दिल्ली सरकार एक फरिश्ते स्कीम लाई हुई थी। फरिश्ते स्कीम ये थी कि आप किसी भी एक्सीडेंट विक्टीम को चाहे वो कोई भी हो दिल्ली का हो, बाहर का हो, अमीर हो, गरीब हो, दिल्ली की सड़क पर अगर एक्सीडेंट हो गया तो आप उसको अस्पताल पहुंचा दो, नियरैस्ट होस्पिटल प्राइवेट होस्पिटल और उसका सारा इलाज मुफ्त किया जाएगा पैसे दिल्ली सरकार देगी। अब अध्यक्ष जी क्या किया एलजी साहब ने आप इसमें समझिए। जो प्राइवेट अस्पताल थे वो पहले ही नहीं चाहते थे कि फरिश्ते की योजना को कोई इम्पलीमेंट करे क्योंकि उनको पैसा मिलता है डीजीएचएस रेट पर। जो उनकी मार्केट रेट से एक बटा दो या कई बार एक बटा तीन होता है। तो वो नहीं चाहते

थे, मगर सरकार ने बहुत ज्यादा अवेरनेस कैंपेन की, अस्पतालों के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बनाया कि भई ये योजना आपको लानी पड़ेगी और ये योजना चली। अब इन एलजी आने के बाद क्या हुआ और इनके आने के बाद ही हुआ है ये साक्ष्य हैं, हमने सुप्रीम कोर्ट में रखे। इनके एलजी बनने के बाद ये हुआ कि हैल्थ डिपार्टमेंट ने उन प्राइवेट अस्पतालों को पैसा देना बंद कर दिया उनके बिलों की पेमेंट करनी बंद कर दी। अब जब बिलों की पेमेंट करनी बंद कर दी तो धीरे-धीरे-धीरे उन्होंने अस्पताल के अंदर फरिश्ते स्कीम के लोगों को deny करना शुरू कर दिया। अब इसका बड़ा असर क्या हुआ अध्यक्ष जी की ऐसे हजारों लोग होंगे, मैं पक्का बता रहा हूं, हजारों लोग होंगे जिन्होंने मानवता की खातिर किसी एक्सीडेंट विक्टीम को उठाया होगा, अपनी गाड़ी में रखा होगा और वो प्राइवेट अस्पताल लेकर गए होंगे। और वहां प्राइवेट अस्पताल ने उनको लिया नहीं होगा, अब तो वो उसके ऊपर पड़ गया ना वो विक्टीम। अब उसने जैसे-तैसे या तो अपनी जेब से उसका ईलाज कराया होगा या वो फिर दुबारा किसी सरकारी अस्पताल में लेकर गया होगा और वो परेशान हुआ होगा और इस परेशानी के कारण अब वो सबको कहेगा कि भई फरिश्ते स्कीम नहीं चल रही अब प्राइवेट अस्पताल मत ले जाना वर्ना मेरी तरह फंस जाओगे। मरे होंगे, बहुत लोग मरे होंगे। जहां पांच-पांच हजार तक फरिश्ते स्कीम के अंदर लोगों का ईलाज हुआ, अब वो इलाज घट के हजार-दो हजार भी नहीं रह गया अध्यक्ष जी। तो मान लीजिए की ऐसे तीन-साढ़े तीन हजार लोग होंगे जो शायद इस फरिश्ते स्कीम के ना चलने की वजह से बेचारे या

तो अपाहिज हो गए होंगे या हो सकता है मृत हो गए होंगे, ये सब किया। होस्पिटलस के अंदर ओपीडी काउंटर के अंदर गरीब डेटा इंट्री ऑपरेटर बैठते थे इन्होंने उनको हटा दिया। डाक स्कीम के अंदर जिस आदमी का टैस्ट सरकारी अस्पताल में ना हो और दो दिन से ज्यादा की डेट मिल रही हो तो वो प्राइवेट लेबोरेटरी में जाकर टैस्ट करा सकता था ये डाक स्कीम थी। किसी की अस्पताल के अंदर ओपरेशन की डेट अगर एक महीने से ज्यादा मिल रही हो सरकारी अस्पताल में तो वो प्राइवेट अस्पताल में जाकर अपना वो ऑपरेशन करा सकता था ये डाक स्कीम है। इन्होंने पिछले डेढ दो साल में डाक स्कीम के पैसे भी अस्पतालों के रोक लिए। उनके बिलों के ऊपर अनाप-शनाप ओब्जेक्शन लगाकर उनके पैसे रोक लिए। तो उन्होंने डाक स्कीम के अंदर भी, जो ऑपरेशंस होते थे वो ओपरेशन करने कम कर दिए। लिहाजा मरीज जो है दरबदर भटक रहे हैं। इस तरीके के काम मैं एलजी साहब को बताना चाहता हूं और उनके साथ जो अफसर रहे हैं मैं उनको बताना चाहता हूं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं इस तरीके के कृत्य आज से पहले किसी एलजी ने नहीं किए, ये इन्होंने ही किए हैं। क्योंकि कोई भी आदमी होगा वो भगवान से तो डरेगा, वो ये तो सोचेगा कि यार कोई आदमी मर जाएगा बेचारा रोड पर तो उसकी मौत मेरे सर पे आएगी। कोई आदमी बिना ऑपरेशन के मर गया होगा तो उसके बच्चों की हाय मुझे लगेगी, ये सोचिये अध्यक्ष जी, मगर इस स्तर तक कोई एल.जी. ने जो है इस बार सत्ता का स्तर नहीं गिराया। दूसरी बात बिधूड़ी जी के यहां भी होगा हमारे यहां भी है हर घर के अंदर

सबको पता है कि जगह-जगह सीवर बह रहे हैं क्योंकि सीवर लाइन बदलने के लिये जल बोर्ड को पैसा नहीं दिया जा रहा। पानी नहीं पहुंच रहा क्योंकि लाइन को रिप्लैस करना हो तो जल बोर्ड को पैसा नहीं दिया जा रहा, ट्यूवेल नहीं हो पा रहे क्योंकि जल बोर्ड को पैसा नहीं दिया जा रहा, ठेकेदारों की एक साल से आपने पेमेंट रोक रखी है। आपने पेमेंट रोक रखी है तो ठेकेदारों ने टेंडर लेना बंद कर दिया ठेकेदार सारे हड़ताल पर चले गये। हाई कोर्ट तक ने कह दिया कि उनकी पेमेंट करो उसके बावजूद भी यहां पेमेंट नहीं होने दे रहे। अब अध्यक्ष जी एल.जी. साहब कहेंगे कि भई इसमें मेरा क्या दोष है। बिधूड़ी जी कहेंगे भई फाइल पर दिखाओ एल.जी. साहब ने कहां लिखा है अरे इतने भी बेवकूफ कोई ना कोई आदमी जो फाइल पर लिख देगा कि अस्पतालों की पेमेंट बंद कर दो, जल बोर्ड की पेमेंट बंद कर दो ये कौन फाइल पर लिखता है। इसका तो बहुत छोटा सा वो है कहते हैं ना 'हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े-लिखे को फारसी क्या' हमने जितने भी इस तरीके के ऑफिसर हैं सबसे बड़े तो इसमें फाइनांस सेक्रेटरी ए.सी. वर्मा जिन्होंने हर चीज़ रोकी। अस्पतालों की पेमेंट उन्होंने रोकी, टैस्ट की पेमेंट उन्होंने रोकी, जल बोर्ड की पेमेंट उन्होंने रोकी, महिलाओं को जो पेंशन मिलती थी बुजुर्गों को वो पेंशन उन्होंने रोकी, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर्स को उनकी वजह से निकाला गया, मोहल्ला क्लीनिक के अंदर डाक्टरों को सैलरी नहीं मिली उनकी वजह से, आप ए. सी. वर्मा को निकालते क्यों नहीं हो? आप ए. सी. वर्मा को नहीं निकाल रहे हैं इस हाउस ने तीन रिपोर्ट दी हैं पिटिशियन्स कमेटी ने 19

जनवरी, 2023 को इस हाउस ने ये रेजुलेशन पास करके तीन reports adopt की हैं जिसके अंदर ए.सी. वर्मा जी के बारे में कहा गया है आपने उनको अभी तक क्यों नहीं सस्पेंड किया? इसलिये सस्पेंड नहीं किया क्योंकि वो आपके चहेते हैं और वो क्यों चहेते हैं क्योंकि आपके कहे हुये काम को कर रहे हैं इसलिये आप उनको सस्पेंड नहीं कर रहे। ये तो जाहिर सी बात है। इसमें मतलब इतना ढूंढना क्या है कि हम एल.जी. साहब के लिखित को दिखायें। बचे हैल्थ सेक्रेटरी, हैल्थ सेक्रेटरी ने सारे के सारे कारनामें किये हैं आपने हैल्थ सेक्रेटरी को अभी तक नहीं निकाला है क्योंकि वो आपके चहेते हैं। बचे रेवेन्यु सेक्रेटरी, डिवीज़नल कमिश्नर जिन्होंने ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी के साथ मिलकर हज़ारों सिविल डिफेंस वॉलेन्टियर्स को निकाल दिया वो आपके चहेते हैं। जो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी थे उनको आपने अपना प्रिसींपल सेक्रेटरी टू एल.जी. लगा दिया। इसका मतलब आपके खास आदमी हैं ना। जिस आदमी ने ये कह कर सिविल डिफेंस वॉलेन्टियर्स को निकाल दिया कि अब सीसीटीवी लग गये हैं अब बस मार्शल की जरूरत नहीं है उस आदमी को आपने सेक्रेटरी टू एल.जी. लगा लिया। इसका मतलब वो आपके खास आदमी हैं। आपको उन्हें निकालना था, आपने उनको अपने घर बुला लिया। तो ये आपकी तो मिली–भगत है। डिवीज़नल कमिश्नर हैं अश्विनी कुमार जी उनको आप नहीं हटा रहे हैं ना आपने उनके ऊपर कार्रवाई की है, क्यों? हां अगर आपको कोई ऑफिसर अच्छा नहीं लगता तो आपने उनके ऊपर कार्रवाई की है। के. महेश थे ऐसे ऑफिसर मैं बताना चाहता हूं कि कुछ मामले थे जिससे एल.जी. उनसे परेशान थे कोई नर्सरी का मामला था, एल.जी. साहब कहीं पर नर्सरी

बनाना चाहते थे वहां पर टॉयलेट्स लगे हुये थे आई थिंक राजेश गुप्ता जी के यहां वजीरपुर का मामला था सबको बताना चाहता हूं वहां पर एल.जी. साहब डीडीए की नर्सरी बनाना चाहते थे वहां पर गरीब लोग शौच करते थे उनके टॉयलेट बने हुये थे। एल.जी. साहब दबाव बना रहे थे कि भई तुम ये टॉयलेट्स हटवाओ यहां मैं नर्सरी बनाऊँगा, फूलों का शौक है एल.जी. साहब को। गरीब कहां जायेगा शौच उससे कोई लेना-देना नहीं है। जायेगा जहां जायेगा, भाड़ में जाये। इस चक्कर में के. महेश साहब से नाराज़गी थी। तो क्या किया एल.जी. साहब ने एक दिन रात को जो है रैन बसैरा देखने आये और बोले अच्छा इतनी गंदी इतनी गंदी चादरें सीईओ डूसिब सस्पेंड रात को सस्पेंड कर दिया। भाई अब गंदी चादर के ऊपर सीईओ डूसिब को सस्पेंड कर सकते हो, पूरी दिल्ली में सीवर बह रहे हैं आपने सीईओ जल बोर्ड को अब तक सस्पेंड क्यों नहीं किया? क्योंकि वो आपके खास आदमी हैं आपके कहने पर काम कर रहे हैं उसमें छुपने की क्या बात है। अगर एल.जी. साहब को ऐसा लगता है हम क्या बेवकूफ हैं। एल.जी. साहब को मैं बताना चाहता हूं यहां पर सब जितने भी विधायक बैठे हैं दो-दो, तीन-तीन बार लाखों लोगों से वोट लेकर आये हैं बेवकूफ नहीं हैं हम लोग सब समझते हैं और जनता भी बेवकूफ नहीं है मैं एल.जी. साहब को बताना चाहता हूं उनके जितने एल.जीयों ने सीसीटीवी रोके, वाईफाई रोके और काम रोके दिल्ली की जनता ने 70 में से 67 सीटें जीता कर भेजा है अरविंद केजरीवाल को ऐसे बेवकूफ नहीं है जनता। इन्होंने खूब काम रोके, खूब परेशान किया अगली बार जनता ने 70 में से 62 सीटें दीं, साफ दीं और वो भी इस वजह से नहीं जो 08 सीटें आईं हैं 08

सीटें भी जिस वजह से आई हैं वो सबको मालूम है कि वो किस वजह से आई हैं वरना वो 08 भी नहीं आतीं ये भारतीय जनता पार्टी को भी मालूम है। उसके लिये उन्होंने स्पेशल प्रोजेक्ट चलाया था उसकी वजह से आई हैं। तो एल.जी. साहब इस गलतफहमी में हैं कि वो जनता को परेशान करेंगे, जनता परेशान हो जायेगी, जनता अरविंद केजरीवाल को गाली देने लगेगी और एल.जी. साहब जो हैं भारतीय जनता पार्टी को जो है ऊपर ले जायेंगे ऐसा कुछ नहीं होने वाला जनता सब समझ रही है जनता को सब समझ में आ रहा है और ये जो 62 विधायक हैं ये जब अपने निकलेंगे ना गली-गली मोहल्ले-मोहल्ले तो सब ये सवाल जो है वो जनता से पूछेंगे जनता को सब समझ में आयेगा। ये जो पत्र एल. जी. साहब ने आपको लिखा और आपके पास पता नहीं रात को पहुंचा है या नहीं पहुंचा मगर ये मिडिया के पास पहुंच गया ये भी एल.जी. साहब से पूछना चाहिये कि भई ऐसा कैसे होता है कि पत्र आप स्पीकर साहब को लिखते हो पर स्पीकर साहब से पहले ये मिडिया में पहुंच जाता है आप तो मिडिया के लिये कर रहे हो ये सारा का सारा posturing कर रहे हैं। हम कर सकते हैं वो कहेंगे तुम भी कर रहे हो हम तो कर सकते हैं हम तो हैं ही आज भी राजनीतिक, हमारा तो काम ही राजनीति करना है, हम तो इलैक्शन लड़ते हैं हम तो बीजेपी को खड़े होकर गाली देते हैं हमारा काम है वो हमें देते हैं उनका काम है। हमें बिधूड़ी जी की गाली से एतराज़ नहीं है वो उनका काम है एज़ ए अपोजिशन वो चिट्ठी लिख सकते हैं मगर एल.जी. साहब ये चिट्ठी लिखें ये एल.जी. साहब एल.जी. के पद की गरिमा को नीचे ला

रहे हैं और मैं उनको करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता ये सब देख रही है आपको इन सब चीज़ों से बचना चाहिये। आज भी समय है एल.जी. साहब के पास, एल.जी. साहब दिल्ली की जनता के हितों के लिये अगर आयेंगे आगे तो दिल्ली की जनता उनको पसंद करेगी उनकी इज्ज़त करेगी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः कल मैं शाम को 4.00 बजे जब मुझे जानकारी मिली ये पत्र एल.जी. साहब से आया है मैं विधानसभा पहुंचा हालांकि मेरे परिवार में दुर्घटना हुई थी तब मैंने पत्र पढ़ा मुझे बड़ा अफसोस हुआ। इसको मैं एक लाइन पढ़कर के सुना रहा हूं। इस प्रस्ताव में जो भी ब्लेम किया गया है वो बीजेपी को किया गया है। 'where the House believes that the opposition party BJP which exercises direct control over the officers of Delhi Govt. and also the Hon'ble LG.' हाउस में बीजेपी को दोषी करार दिया गया है एल.जी. साहब को कहीं दोषी करार नहीं दिया गया है, पता नहीं उनको क्यों पीड़ा हुई, क्यों परेशानी हुई। ये बड़ी अजीब सी बात है एक बात दूसरी बात, हाउस में जो भी चर्चा होती है जो भी विषय रखे जाते हैं बिधूड़ी जी उस वक्त यहां रहे होंगे इन्होंने एक्सेप्ट किया उसका हाउस में पास हुआ इन्होंने कोई क्वेश्चन रेज़ नहीं किया कि लाइन हटाई जाये, तीसरी बात मैं नाम नहीं ले रहा हूं भारत के सर्वोच्च लोकतंत्र के मंदिर लोकसभा, राज्यसभा में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिज़ के विषय में जो-जो टिप्पणियां की जाती हैं उनको कौन देखेगा कौन उन पर विचार करेगा? ये एल.जी. साहब से जो पत्र लिखा है और मैं मुझे कहते हुये बड़ा अफसोस हो

रहा है कि मेरे अपने राजनैतिक जीवन में हालांकि मैंने पूछा था मैं बोलूंलेकिन अब मेरा मन नहीं मान रहा, मैं बोल रहा हूं। पंजाब की गर्वमेंट को वहां के गर्वनर के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट बार-बार जाना पड़ा। तमिलनाडू के गर्वनर का क्या रवैया है ये सर्वविदित है। गर्वनर्स क्या-क्या रोल किस-किस स्टेट में अदा कर रहे हैं ये सर्वविदित है और जो कुछ सौरभ जी ने कहा है उसमें एक लाइन और जोड़कर मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं मेरी अपनी विधानसभा में दो शौचालयों की बिजली काट दी गई। मुझे मालूम है कि किस ढ़ंग से जनरेटर लगाकर बिजली दी गई फिर मैंने सीईओ से बात करके अपनी गारंटी पर लैटर लिखकर वो लैटर है मैं सदन पटल पर लिख सकता हूं कि 'I take the guarantee to make the payment within 15 days' अगर डूसिब पेमेंट नहीं करता। अब जाकर के intervene करने के बाद वो 1 लाख का एक शौचालय का बिल एक का 2 लाख का बिल वो पेमेंट हुआ है और 1 लाख का बिल कोई एक दिन का नहीं है एक-एक साल के बिल पैंडिंग हैं डेढ़-डेढ़ साल के पैंडिंग हैं। जल बोर्ड की हड़ताल जो एक साल से चल रही है लोग दु:खी हैं इस बात से परेशान है बहुत बुरा, तो एल. जी. साहब को ये दिखना चाहिये दिखाई देता है तो ये चिट्ठी अपने आप में निदंनीय है। एल.जी. साहब को चाहिये था इस पीड़ा को दूर करने की बजाय आग में घी डालने का काम हुआ है और ये मैं भी स्वंय इस पर इस चिट्ठी से पीड़ित हूं। संजीव जी के प्रस्ताव के लिए वोटिंग, सदन सहमत है तो, करवा दी जाये। संजीव जी का प्रस्ताव सदन के सामने है

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

माननीय सदस्यों से मेरी प्रार्थना है कि 280 चूंकि इसपर समय बहुत हो गया है। जितना लिखा है अक्षर-अक्षर वही बोलेंगे उससे ऊपर एक शब्द मैं स्वीकार नहीं करूंगा बहुत-बहुत धन्यवाद, श्रीमान महेंद्र गोयल जी ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा ले सकूं।

विशेष उल्लेख (नियम-280)

श्री महेंद्र गोयलः धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी कंझावला रोड़ के ऊपर मेरे बुद्ध विहार के एरिये के साथ-साथ में एक नाला बना हुआ है और नाले की उसकी जर्जर हालत हो गई है उस पर वो आर.सी.सी. का नाला बनाना है काफी समय से वो पैंडिंग है साइड की बरम लगानी है। लोगों का निकलना बड़ा दुश्वार है तो मैं बहुत ज्यादा ना बोलते हुये आपसे बस यही आग्रह करूंगा और ये सभी को प्रतीत हो रहा है कि पीडब्ल्यूडी के कामों को कैसे रोका जा रहा है जल बोर्ड के कामों को कैसे रोका जा रहा है। आपकी तो पेमेंट कर दी आपके लैटर के बाद। उन लोगों

का क्या है कि जो जल बोर्ड का काम करे या पीडब्ल्यूडी का काम करे उनकी आज तक कोई पेमेंट नहीं हुई।

माननीय अध्यक्षः महेंद्र जी अब हो गया बस प्लीज़।

श्री महेंद्र गोयलः बस ये मेरा नाला बनवा दें xxx[2] ताकि वहां की जनता आपका धन्यवाद करने के लिये यहीं पर आ जाये।

माननीय अध्यक्षः ये यार शब्द निकाल दिया जाये कार्यवाही से।

श्री महेंद्र गोयलः हां जी अध्यक्ष जी, आश्वासन दे दूं मैं अपनी जनता को कि अध्यक्ष जी के intervene के बाद ये काम हो जायेगा।

माननीय अध्यक्षः प्रयास..।

श्री महेंद्र गोयलः क्योंकि काम रोकने का काम कर रखा है इन लोगों ने।

माननीय अध्यक्षः चलिये श्री हो गया अब महेंद्र जी हो गया, श्री प्रलाद सिंह साहनी जी।

श्री महेंद्र गोयलः धन्यवाद जी।

श्री प्रलाद सिंह साहनीः अध्यक्ष जी, आपने मेरे को समय दिया मैं आपका धन्यवाद करता हूं हमारे यहां military के लोग रहते हैं और कच्चे-पक्के पकानों में झुग्गियों में रहते हैं। आज से कोई पचास-पचास, साठ-साठ साल से वो उन जगहों पर रह रहे हैं वहां ना सीवर है,

---

[2] चिन्हित अंश अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से निकाले गए।

पानी की दिक्कत हो रही है इतनी कि लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता। सीवर लाइनें सफाई करने जायें तो military के लोग आ जाते हैं उसको रूकवा देते हैं। हम पानी की लाइन डलवाते हैं तो वो आ जाते हैं ऐसी समस्या से वो लोग जुझ रहे हैं इस हाउस के मार्फत में ये कहना चाहता हूं कि अगर उस जगह को कभी भी military वालों ने उठाना हो उठा लें मगर बेसिक फैसेलिटी पानी, सीवर, सफाई की समस्या जो है उसको बहुत जल्द से जल्द उसको ठीक कराना चाहिये दूसरी मेरी ये प्रपोज़ल थी कि दिल्ली के अंदर जहां मुस्लिम बस्तिज़ हैं जहां मुस्लमान भाई रहते हैं जामा मस्ज़िद, नवाबगंज, टोकरीवालान इधर-उधर जितने भी एरिये हैं उनके अदंर हम 10 दिन पहले 15 दिन पहले सफाई का इंतज़ाम करते थे। हर गलियों के बाहर बड़े जो रोड्स होते हैं उनके ऊपर super sucker machines लगाई जाती थीं जो दो-दो फर्लांग दूर से भी पानी को गंदे पानी को सिल्ट को निकालकर ले जाया करती थीं उससे ये फायदा होता था तमाम छोटी-छोटी गलियां बिल्कुल एकदम साफ हो जाती थीं। आने वाले दिनों का जब रमज़ान होता था उन दिनों के अंदर एक बूंद भी गंदा पानी कहीं नहीं जाता था कहीं गली के अंदर कोई सीवर लाइन बंद नहीं होती थी, साफ-सुथरा पानी मिलता था और लोगों को दिक्कत नहीं थी। आज ये पोजिशन है कि तमाम गलियां मुस्लिम बस्ती की बंद हैं सीवर लाइन के अंदर पानी भरा हुआ है कीचड़ भरी हुई है जब तक हमने कई दफा जल बोर्ड को कहा कि आप इसमें super sucker लगाईये super sucker लगाने से दिल्ली के अंदर जितनी भी गलियां नज़दीक की छोटी गलियां हैं यहां

मशीनें नहीं जा सकतीं वहां super sucker बाहर से लगाते हैं तो फर्लांग वो दूर का मलबा वो निकाल देते हैं और आने वाले दिनों के अंदर जब रमज़ान होगी उनको पाकपानी मिलेगा, वज़ू करने के लिये पानी मिलेगा और पानी पीने के लिये भी साफ मिलेगा ऐसा मेरा मानना है। इस हाउस के मार्फत में ये कहना चाहता हूं कि हमारे मंत्री साहब को ये आदेश दिया जाये मंत्री साहब नीचे आदेश दें कि ये super sucker जल्द से जल्द जहां-जहां मेरे ही नही तमाम जितने दिल्ली के मुस्लिम एरिया हैं उनके अंदर लगा दिया जाये 10-12 दिन के अंदर-अंदर मेरा ख्याल है रमज़ान शुरू होने वाले हैं उनसे पहले-पहले अगर ये लगा दी तो ना तो उनको गंदा पानी मिलेगा और ना सीवर लाइनें मिलेंगी और दूसरी चीज़ ये पानी की समस्या जो है।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद साहनी जी, साहनी जी हो गया।

श्री प्रलाद सिंह साहनीः एक सैकेंड और है जी। पानी की समस्या जो है हर दफा जो मुस्लिम बस्तियां होती थीं उनको रमज़ान के दिनों में एक्स्ट्रा पानी दिया जाता था। आज भी मैं आपसे सदन के मार्फत मैं यही कहना चाहता हूं कि जितना भी मुस्लिम बस्तियों को रमज़ान के दिनों में पानी मिल सके उतना मिलना चाहिये ताकि नमाज़ी अपनी नमाज़ ठीक तरह से अदा कर सके वज़ू का पानी को नहाने का पानी हो वज़ू के लिये पानी हो तमाम चीज़ें मिलनी चाहियें और उसके जितने भी उस एरिये में पानी नहीं मिल रहा है उनके ट्यूवेल जो लगे हुये हैं तमाम ट्यूवेल ठीक कर दिये जायें ताकि लोगों को दिक्कत ना हों, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्री नरेश यादव जी, कृपया नरेश जी पढ़ियेगा जो लिखा है।

श्री नरेश यादवः ठीक हैं, अध्यक्ष जी धन्यवाद जो आपने मुझे मेरे क्षेत्र की समस्या उठाने का मौका दिया अध्यक्ष जी महरौली एक ऐतिहासिक शहर है सभी जानते हैं कुतुबमीनार वर्ल्ड फेमस है इसके अलावा जमाली कमाली, जहाज़ महल, जफ़र महल, झरना, शमशी तालाब, कुलीखान टॉम्ब, बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक मौनूमेंट्स वहां पर हैं और बहुत सारे टूरिस्ट वहां पर आते हैं इसके अलावा वहां पर एसडीएम ऑफिस है एसआर ऑफिस है। अध्यक्ष जी महरौली के अंदर पार्किंग की एक बहुत बड़ी समस्या है और लगभग महरौली के अंदर जो टाउनशिप है उसके दो-ढाई लाख लोगों की आबादी है आजकल सभी परिवारों के पास गाड़ियां हैं। अध्यक्ष जी, महरौली इस तरह से डव्लप हुआ है कि उसके चारों तरफ संजय वन है और डीडीए लैंड्स है तो मेरा आपके माध्यम से ये अनुरोध है डीडीए लैंड, पब्लिक लैंड है और डीडीए की लैंड पब्लिक के लिये इस्तेमाल होनी चाहिये। जैसा कि आज एल.जी. साहब की चिट्ठी पर अभी चर्चा हुई है वो निंदा प्रस्ताव पास हुआ है। एल.जी. साहब को ये सब काम करने चाहिये दिल्ली की जनता के लिये कि जो डीडीए की लैंड है उसका कहां सद्उपयोग हो सकता है उसका उपयोग होना चाहिये। डीडीए की चारों तरफ लैंड है किशनगढ़ साइड मे भूल-भुलैया साइड में, अंधेरिया मोड़ साइड में और दादाबाड़ी मंदिर साइड में, चारों तरफ अगर छोटी-छोटी पार्किंग्स बना दी जाये तो महरौली की पार्किंग की समस्या निपट सकती है। अध्यक्ष जी

मैं आपके माध्यम से यही अनुरोध करूंगा कि महरौली की पार्किंग की समस्या जल्दी से जल्दी उस पर काम किया जाये और ये यहां का मैसेज एल.जी. तक भी जाये ये मैं उम्मीद करता हूं, बहुत-बहुत शुक्रिया अध्यक्ष जी जो आपने मुझे मेरी समस्या उठाने का मौका दिया।

माननीय अध्यक्षः अजय दत्त जी।

श्री अजय दत्तः जी धन्यवाद आपका आपने मुझे मेरे क्षेत्र की गंभीर समस्या पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, अम्बेडकर नगर में सी-ब्लॉक में एक UGR है और एक पानी की टंकी है। अध्यक्ष जी, ये पानी की टंकी पिछले 15 साल से जर्जर हालत में है और इसकी वजह से मेरे क्षेत्र में कभी भी अगर वो गिर गई तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। मैने जल बोर्ड के अधिकारियों को कई बार सूचित किया कि जर्जर टंकी को तोड़ दिया जाये और उसकी जगह एक नया यूजीआर बना दिया जाये जिससे कि लोगों को पानी की भी व्यवस्था हो जाये और ये जो बड़ा संकट अम्बेडकर नगर और सी-ब्लॉक के लोगों के ऊपर है। अगर टंकी टूटी गई तो ये बहुत बड़ा ईशू आ जायेगा। तो मैं आपके माध्यम से ज्यादा समय ना लेते हुए इतना ही कहना चाहता हूं कि जल बोर्ड के अधिकारियों को आप आदेश दें कि ये जो खतरे की घंटी खड़ी हुई है जिसके आसपास कई हजार लोग रहते हैं इसको जल्द से जल्द तोडकर वहां एक नई यूजीआर का निर्माण किया जाए, जिससे वहां के लोगों की पानी की समस्या भी दूर हो और ये जो खतरे की घंटी टंकी के रूप में खड़ी है, इससे निजात मिले। अध्यक्ष जी आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक्यू।

माननीय अध्यक्षः प्रमिला टोकस जी।

श्रीमती प्रमिला धीरज टोकसः धन्यवाद अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी मेरी आर.के.पुरम विधान सभा में अक्सर वहां के स्थानीय लोगों की शिकायत मिल रही है कि जब वे बिजली के नये कनैक्शन के लिए अप्लाई करते हैं तो नया कनैक्शन लगवाने में बीएसईएस दोबारा अलग–अलग तरीको से उन्हें तंग किया जाता है। काफी जगह से तो मीटर कनैक्शन देने से मना किया जाता है। गांव के अंदर लोगों के पास अपनी पुस्तैनी जमीन होती है। जिसके कोई दस्तावेज उनके पास नहीं होता या गांव के एक ही आदमी के कई मकान होते हैं और वह दूसरी बिल्डिंग का कनैक्शन लेना चाहता है तो उन्हें कनैक्शन नहीं दिया जाता। उन्हें बोल दिया जाता है कि आप हर मकान का पता बदलवाओ तभी जाकर हम आपको नया कनैक्शन देंगे। जैसे कि एक स्थानीय निवासियों के चार मकान है और अगर उसे अपने किसी और मकान में नया कनैक्शन लेना है तो क्या हर बार वह अपने दस्तावेज में अपने पते को बदलवाता रहेगा। क्या तभी जाकर उन्हें बीएसईएस द्वारा नया कनैक्शन मिलेगा। अध्यक्ष जी इस पर संज्ञान लीजिए। अध्यक्ष जी मेरी विधान सभा में पीडब्ल्यूडी द्वारा पांच फुट–ओवर ब्रिज बनाये हैं और उसमें लिफ्ट नहीं लगाई है। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है मंत्री जी से उसमें लिफ्ट लगाकर और वो जनता को समर्पित किया जाये। धन्यवाद अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः श्री गौतम जी।

श्री राजेन्द्र पाल गौतमः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान मेरी विधान सभा के अंदर एक फ्लाई ओवर रेलवे ब्रिज पर, रेलवे लाइन के ऊपर से बना था, उसके ऊपर ले जाना चाहता हूं। ये जो दुर्गा पुरी चौक से नन्द नगरी डीसी ऑफिस की तरफ जो रोड जाता है, उसमें रेलवे लाइन पर फ्लाई ओवर बना था। माननीय अध्यक्ष जी, सारी बसें वहीं से गुजरती थी। इतना मतलब शर्मनाक है मुझे दुख भी होता है कई बार कि वो फ्लाई ओवर इतना घटिया क्वालिटी का बना जबकि सीपीडब्ल्यूडी मैनूअल में तो बहुत excessive side रेट होते हैं और उससे बनने के कुछ ही साल में मतलब कुछ टाइम भी नहीं हुआ छः सात साल के अंदर उस पुल में दरारें पड़ गई।

माननीय अध्यक्षः कौन से साल में बना था ये।

श्री राजेन्द्र पाल गौतमः 2008 से 2013 के बीच-बीच में बना और इतनी जल्दी बनने के बाद उस पर बसें चला करती थी। मुश्किल से पांच साल हुए होंगे बसों को चलते हुए उस पुल के अंदर दरारें आ गई। दरारें आने के बाद वहां से पूरे वाहनों का निकलना बंद कर दिया। भारी वाहन बिल्कुल बंद कर दिये। दोनों तरफ लोहे के बैरिकेट लगाकर केवल वहां से अब छोटे वाहन चल सकते हैं। छोटे वाहन में भी कारें और बाईसिकल या टू-व्हीलर्स। तब से कई साल से वो लगातार बंद पड़ा है। मुझे इस बात का दुख है कि उसकी जांच का क्या हुआ आज तक पता ही नहीं चल रहा। उसमें करोड़ों रूपये ठेकेदार ने इंजीनियरों ने मिलकर खाये होंगे। लिकर पॉलिसी जो फर्जी पॉलिसी

जिसमें कोई घोटाला नहीं हुआ और उसमें हमारे नेता जेल के अंदर पड़े हुए है, साल से ऊपर हो गया और इधर इतना बड़ा घोटाला करोड़ों रूपयों का हो गया उसमें अब तक कोई जांच ही नहीं है कुछ पता ही नही लग रहा। वो पुल बंद पड़ा है, वो पुल चलना चाहिए, बसें बंद है। उधर नन्द नगरी की तरफ भी फ्लाई ओवर बन रहा है तो उधर भी बसें नहीं जा पा रही। तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं, अपने यूडी मिनिस्टर साहब से कि इसकी पूरी जांच जल्दी से करवाकर ऐसे लोगों को जेल में डलवाने का इंतजाम किया जाए और उस पुल को दोबारा से चालू करवाया जाये। उसका पुरा अच्छे से रिपेयर करवा कर वो जल्दी से जल्दी वो पुल चालू हो ताकि लोग वहां से निकल सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्रीमान बिधूड़ी जी।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (नेता प्रतिपक्ष): बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। आदरणीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से आम आदमी पार्टी सरकार का ध्यान दिल्ली देहात और दिल्ली के किसानों की गम्भीर समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी.

माननीय अध्यक्षः साहनी जी प्लीज।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः गावों का लाल डोरा बढ़ाया जाये। 2012, 2013 में सरकार ने ये फैसला ले लिया था किसान की यदि मृत्यु हो जाती है तो उनके बेटा या बेटी के नाम रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जमीन ट्रांसफर नहीं हो रही है। आदरणीय जिन किसानों की जमीन

एक्वायर की जाती है उनको alternative residential plot दिया जाता है। वह भी बंद कर दिया गया है। दिल्ली में कृषि यंत्रों पर सब्सिडी नहीं दी जा रही है। ट्रेक्टर को commercial vehicle घोषित कर दिया गया है उस श्रेणी में रख दिया गया। तो मैं चाहूंगा कि उस श्रेणी से ट्रैक्टर को निकाला जाये और किसान यदि ट्रैक्टर खरीदे तो उसके ऊपर सरकार सब्सिडी दे। आदरणीय अध्यक्ष जी, अभी भी लगभग डेढ़ सौ गावों में खेती बाडी होती है। किसान अपने खेत में सिंचाई के लिए ट्यूबवेल लगा नहीं सकता, उसकी अनुमति मिलती नहीं। ट्यूबवेल लगा है तो उसके लिए कनैक्शन मिलता नहीं। हरियाणा और पंजाब में किसान को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाती है। मैं आपके माध्यम से दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जिस तरह से हरियाणा और पंजाब में सिंचाई के लिए किसानों को मुफ्त बिजली दी जा रही है, दिल्ली के किसानों को भी मुफ्त बिजली दी जाए। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरी बात से सभी ऑनरेबल एमएलए सहमत होंगे। 20 प्वाइंट प्रोग्राम के तहत दिल्ली में हजारों भूमिहीनों को residential और खेती बाडी के लिए जमीन सरकार के द्वारा दी गई। लम्बे समय से वो मांग कर रहे है और ऑनरेबल चीफमिनिस्टर की भी ये commitment थी कि हम इनको मालिकाना हक देंगे। तो मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि भूमिहीनों को मालिकाना हक दिया जाये। हाल ही में 22 दिसम्बर,...

माननीय अध्यक्षः बिधूड़ी जी.

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः मेरा ये है आप देख लें। 22 दिसम्बर, 2022 को नंगली गांव में किसानों की जमीन 22 लाख रूपये एकड़ के हिसाब से एक्वायर की गई है। ये राशि बहुत कम है। किसानों की लूट है इसको सरकार को रोकना चाहिए और दिल्ली में पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लागू करना चाहिए। ये मैं आपके माध्यम से दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं। अध्यक्ष जी आपने मुझे समय दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्री सोम दत्त जी।

श्री प्रलाद सिंह साहनीः मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है। हम सब बिधूड़ी के साथ है। बिधूड़ी जी को किसान रैली में जाना चाहिए और खड़े होकर ये कहना चाहिए मैं किसान का पुत्र हूं। मैं किसान की हर demand के साथ चलूंगा। आप रैली करवाईये।

माननीय अध्यक्षः हंसी मजाक में हो गया।

श्री रामबीर सिंह बिधूड़ीः अध्यक्ष जी किसान रैली मैं आयोजित करूंगा और उसमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को भी और ऑनरेबल साहनी साहब को भी बुलाऊंगा।

माननीय अध्यक्षः चलिए धन्यवाद। श्री सोमदत्त जी।

श्री सोम दत्तः धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी मैं आपका ध्यान यूडी डिपार्टमेंट एमएलए फंड केसेज की ओर दिलाना चाहता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि यूडी डिपार्टमेंट ये ठान लिया है कि अब किसी

एमएलए के एक भी केस को सैंक्शन नहीं दी जायेगी और मैं इसके कुछ साक्ष्य रखूंगा आपके सामने अध्यक्ष जी। इसके लिए खास तौर पर दो तो मैं आर्डर बताऊंगा आपको 26 फरवरी की डेट का आर्डर बताऊंगा और 27 फरवरी 2024 की डेट के जो भी नए सर्कूलर निकाले हैं। साथ में इन्होंने जो मुझे एक लैटर दिया है डिपार्टमेंट ने मैं भी वो भी आपको बताना चाहता हूं और ये सब इसलिए किया जा रहा है कि ताकि किसी भी एमएलए का एक भी केस सैंक्शन ना हो सके।

माननीय अध्यक्षः प्रमिला जी बैठिये।

श्री सोम दत्तः इतनी hurdle… इतनी hurdle create की जा रही है अध्यक्ष जी। एमएलए लैड फंड के अलावा एमपी लैड फंड होता है। मैं जानना चाहता हूं क्या वहां ऐसी शर्ते लागू हैं। काउंसलर लैड फंड होता है, मैं जानना चाहता हूं क्या वहां ऐसी शर्ते लागू हैं। दस साल हमें एमएलए बने हुए हो गए क्या दस साल से ऐसी शर्ते लागू थी। ये सब intentionally किया जा रहा है, जानबूझकर किया जा रहा है। ताकि किसी भी एमएलए का एक भी, एक भी एमएलए फंड का केस सैंक्शन ना हो सके। ये सर्कूलर ये सब एग्जाम्पल हैं इसके अध्यक्ष जी। आप यूडी डिपार्टमेंट किसी व्यक्ति को भेजिये जाकर देखिये आज की डेट में वहां कितनी पेंडेसी है और ये कब से है पेंडेसी। ये पिछले कुछ महीनों से अध्यक्ष जी। intentionally किया जा रहा है जानबूझकर ये सब और पब्लिक के काम रोके हुए हैं। इन सर्कूलर के माध्यम से ये देखिये ये 26 फरवरी का सर्कूलर है अध्यक्ष जी जो ये कहता है कि कोई भी executing agency एजेंसी नया

एस्टीमेट जब तक सब्मिट नहीं करायेगी जब तक वो पूराने काम का सैकेंड बिल पे नहीं कर देगी। अध्यक्ष जी किसी काम को कराने के लिए क्या एक ही दिन में कोई काम हो जाता है। ये सैंक्शन निकालते हैं एक-एक महीने तक उस सैंक्शन की पेमेंट executing agency पर नहीं आती। टेंडर नहीं लग पाता एक-एक महीने तक। जब तक यूडी से पेंमेंट ही नहीं पहुंचेगी उस executing agency को टेंडर कैसे लगेगा। और उस टेंडर के वर्क अवार्ड होने तक छः महीने लग जाते हैं। तो तब क्या छः महीने तक एक साल तक वो executing agency नया अस्टीमेट सब्मिट करायेगी अध्यक्ष जी। बारात घर बनने के लिए एक-एक साल लग जाते हैं। तब तक क्या वो executing agency नए अस्टीमेट सब्मिट करायेगी क्या। तो ये सिर्फ काम रोकने की साजिशें है, ये जितनी भी साजिशें हैं। ये जीओ टैंगिग का एक सर्कूलर आया हुआ है 27 फरवरी की डेट का। एमपी फंड में, काउंसलर फंड में वो भी तो काम कराते हैं। वहां ऐसे सर्कूलर क्यों नहीं आते। एक बार केन्द्र सरकार में लगा के देखें इनको पता चल जायेगा क्या स्थिति होती है। वहां भी तो इनके डिपार्टमेंट हैं एक बार लगाये एमपी कपड़े फाड़ देंगे इनके। पता चल जायेगा वहां भी कोई डिपार्टमेंट होता है कि नहीं होता और ये एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। ये एक लैटर मुझे दिया है इन्होंने ये 07 फरवरी को। ये मैंने पीडब्ल्यूडी से बैडमिंटन कोर्ट बनवाने का लगाया था। अस्टीमेट में executing agency पीडब्ल्यूडी है, जगह भी पीडब्ल्यूडी की है, अस्टीमेट में सबकुछ क्लीयरली मैंशन्ड किया हुआ है। उसके बावजूद भी ये confirmation चाहते हैं कि ये जगह आपकी

है। मैं यूडी के अंदर गया डिप्टी सैक्रेट्री जो हैं उनसे बात किया। भई वो लिख कर दे रहे हैं, वो लिखकर दे रहे हैं आपको लिखे हुए के ऊपर क्या सबूत चाहिए। लिखी हुई बात तो सुप्रीम होती है अपने आप में फिर अब आप कौन सा सबूत चाहते हैं। जब पीडब्ल्यूडी लिख रहा है कि हमारे लैंड है हम बनाना है अब क्या तसल्ली करोगे, कैसे तसल्ली होएगी इन बातों की। तो मेरा आपसे कहना है कोई सिस्टम होना चाहिए वर्ना एक रूपया भी किसी एमएलए का आने वाले पूरे साल में execution नहीं हो पायेगा। मेरी रिक्वेस्ट है और मेरे साथ ये सारे जितने विधायक हैं आप पूछिये एक भी सैंक्शन नहीं हो पायेगी। कई महीनो सो रोक रखी है। वहां इतनी पैंडिंसी हो गई है जनता के जितने जरूरी काम हैं एमएलए फंड के वो रूके हुए है। लोग हमारे को पकड़ रहे हैं गलियों में। किसके पास जायें, किससे कहें कि ये एमएलए फंड के काम कहां से होंगे, कब होगें।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः ये जो लैटर आया है सोमदत्त जी ये सदन पटल पर दे दीजिए आपके पास जो है।

श्री सोम दत्तः ठीक है अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः बैठिये एक बार। देखते हैं क्या कर सकते हैं। बात करता हूं।

(सभी सदस्य इस बात पर पर अपनी भावना व्यक्त करते हुए)

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यों ने अपनी भावना रख दी। मुझे समय दीजिए क्या करना है।

श्री अजय दत्तः अध्यक्ष जी इसे पैटिशन में भेजिये। अध्यक्ष जी मैं कुछ दिन पहले गया एक अधिकारी से मिला...

माननीय अध्यक्षः भई इस पर चर्चा नहीं मांगी है। मैं इस पर चर्चा अलाऊ नहीं कर रहा हूं। आपने अपनी भावना व्यक्त कर दी। आपने अपनी भावना व्यक्त कर दी। मुझे समय दीजिए मैं क्या कर सकता हूं इस पर।

श्री अजय दत्तः इसको पैटिशन कमेटी में भेज दीजिए।

माननीय अध्यक्षः करता हूं।

श्री सोम दत्तः धन्यवाद अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः पवन शर्मा जी।

श्री पवन शर्माः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मेरे क्षेत्र की समस्या उठाने का अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आदर्श नगर विधान सभा के भडौला गांव की तरफ दिलवाना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, आजाद पुर मंडी से भडौला गांव में पहले तीन गेट होते थे और वो तीनों को बंद कर दिया गया है। ये सवाल मैने पहले भी उठाया था। अध्यक्ष जी आजाद पुर रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन पर जाने का रास्ता भी आजाद मंडी के अंदर से होकर गुजरता है। तो गांव के लोगों को स्टेशन पर जाने में दिक्कत होती है। अध्यक्ष महोदय,

आजाद पुर मंडी के अंदर एक गांव का प्राचीन मंदिर है। लोगों की आस्था का सवाल है, उस मंदिर में पूजा अर्जना करनी होती है। महिलायें गावं के लोग वहां पर जाने में दिक्कत होती है। तो अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि कृपा करके एक छोटा गेट, भले ही छोटा गेट एक खुलवा दिया जाए। जिससे केवल आदमी अंदर जा सके या जिग-जैग वाला गेट खुलवा दिया जाये जिससे गाय या पशु कोई अंदर ना जा सके। इसमें भी समस्या का समाधान निकाला जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। ध्यानाकर्षण नियम 54 के अन्तर्गत श्री जरनैल सिंह जी माननीय सदस्य, माननीय उप-राज्यपाल द्वारा दिल्ली परिवहन निगम की बसों में तैनात मार्शलों को हटाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा करेंगे, श्री जरनैल सिंह जी।

श्री बी एस जूनः सर मेरा लास्ट रह गया है।

माननीय अध्यक्षः नहीं प्लीज। मैं डेली लेता आज समय देख लीजिए।

श्री बी एस जूनः सर दो मिनट से ज्यादा नहीं ...

माननीय अध्यक्षः नहीं अब नहीं मैं फिर सबके लेने पड़ेगे मुझे।

श्री बी एस जूनः तभी तो कह रहा हूं एक मिनट में कन्क्लूड कर दूंगा।

माननीय अध्यक्षः जून साहब मैं डेली लेता हूं। आज मानिये प्लीज। मेरी बात मानिये आज।

ध्यानाकर्षण (नियम–54)

श्री जरनैल सिंहः नियम 54 के तहत दिल्ली के एलजी साहब द्वारा डीटीसी की बसों में तैनात बस मार्शल्स को हटाये जाने के इस गम्भीर मामले पर इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में समय देने के लिए बहुत–बहुत धन्यवाद स्पीकर साहब। सर हर साल दो करोड रोजगार देने वाली पार्टी के इशारों पर जब दिल्ली के युवाओं का रोजगार छीना जाना लगे तो ये अपने–अपने में एक शर्मनाम बात है और बहुत गम्भीर स्थिति उत्पन्न इस वजह से हुई पड़ी है कि दिल्ली सरकार ने, दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने 2015 के अंदर 11 मई, 2015 को दिल्ली में, दिल्ली की बसों को, दिल्ली की बसों में ट्रैवल करने वाले यात्रियों को एक सुरक्षित माहौल देने के लिए उसमें बस मार्शलों की तैनाती के लिए एक बैठक बुलाई जिसमें खुद गृह मंत्री ये बैठक बुलाई थी। स्पीकर साहब एक समय होता था जब भाजपा में कुछ अच्छे नेता होते थे, किरदार वाले नेता होते थे। हमारे देश के पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि पार्टी को तोड़कर अगर सत्ता आती है तो ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा, आज कल ये ऐसी सत्ताओं के पीछे ही भाग रहे हैं। अभी कल भी हमने हिमाचल में देखा। उन्होंने बोला था जो कल थे वे आज नहीं है जो आज है, वे कल नहीं होंगे। होने ना होने का क्रम ऐसे चलता रहेगा। हम थे, हम रहेंगे ये भ्रम भी यूं ही पलता रहेगा। तो स्पीकर साहब उसूलों वाली होती थी पर आजकल उसूल दूर–दूर तक भाजपा में नहीं दिख रहे। ये सवेरे–सवेरे पार्क से एक ट्रेनिंग लेकर आते हैं कि हमें

देश को बदलना है, हमें देश की सेवा करनी है। अब कहीं तो इन्हें मौका दे देती है उसके लिए चुनाव लड़ते हैं, जनता मौका दे देती है कि कर लो। वहां की बदहाली भी हम देखते हैं, कहीं जनता मौका नहीं जैसे दिल्ली में नहीं दिया। एक बार दे दिया, दो बार दे दिया, तीन बार दे दिया और ये तो ठान चुके होते हैं हमें सेवा करनी है हमें बेड़ा गर्क करना है। तो जहां मौका नहीं मिलता जहां जनता नहीं चुनती वहां फिर ये कभी-कभी चण्डीगढ़ जैसे एक्सपैरिमेंट भी करते हैं कि नतीजे ही बदल दो। उसके बाद भी बात नहीं बनती तो Lt. Governor के माध्यम से किस तरीके से स्टेट के कामों में interfere कर रहे हैं वो अपने आप में सारे देश के एक बहुत अंदर खराब माहौल बना चुका है। हर दिन constitution की धज्जियां उड़ा कर un-constitutional ऐसे लैटर्स गवर्नर और एलजी साहब के माध्यम से भेजे जाते हैं। हम खुद फेस कर रहे हैं। ईवन स्टेट्स के अंदर जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां इस तरीके की interference देखी जा रही है। तो 11 मई, 2015 की इस बैठक के बाद स्पीकर साहब बस मार्शलों की कानूनी स्थिति पर आपत्ति और सवाल उठाते हुए डायरेक्टर होमगार्ड को एक ऑफिस लेटर जारी किया गया। 17 जून, 2015 को उन्होंने उनको निर्देश दिये गए मंत्री जी की तरफ से कि दिल्ली की बसों में 4000 होमगार्ड की भर्ती की जाए। पर 18 जून को कहते हैं कि हम 4000 हजार नहीं दे सकते हम 2000 ही पायेंगे। फिर दिल्ली के सीएम साहब एक मीटिंग करते हैं और कहते हैं कि दिल्ली के लोगों की जो बसों के अंदर सुरक्षा है वो बहुत जरूरी है तो उस मीटिंग के अंदर वो भी एल्टरनेट

व्यवस्था खोजते हैं कि चलो सिविल डिफेंस के जो वॉलिंटियर्स हैं उनको क्यों ना इन्रोल कर दिया जाए। सिविल डिफेंस वॉलिंटियर्स की अगर बात करूं स्पीकर साहब तो ये वो वॉलिंटियर्स हैं जब कोविड का दौर चल रहा था तो इस दौर के अंदर घरों के अंदर जो लोग थे कोविड के मरीज वो उनको खाना पहुंचाने से लेकर वैक्सीनेशन के दौर में जब लोग खुल के बाहर नहीं निकलते थे तब तक सारी डयूटीज इन सिविल डिफेंस वॉलिंटियर्स ने बखूबी निभाई है। इसके बाद लगातार ये सिलसिला चलता गया स्पीकर साहब आगे बढ़ता गया। फिर एक बार इनकी तरफ से बोल दिया जाता है कि बसों के अंदर तो पैनिक बटन भी लगे हैं और सीसीटीवी कैमरा भी लगे हैं। सीसीटीवी कैमरा का अपना रोल है स्पीकर साहब और पैनिक बटन का अपना रोल है। ये बाद में क्राइम कंट्रोल करने में तो सीसीटीवी कैमरा सहायक हो सकता है।

माननीय अध्यक्षः जनरैल जी कन्क्लूड करिये प्लीज।

श्री जरनैल सिंहः पर उससे क्राइम रोका नहीं जा सकता। स्पीकर साहब मैं अपनी बात चर्चा की शुरूआत में तीन पॉइंट्स पर लाकरकन्क्लूड करना चाहता हूँ कि 2015 से लेकर 2022 तक ये स्कीम चली। अब ये कोई 1968 सिविल डिफेंस एक्ट का हवाला दे रहे हैं कि सिविल डिफेंस एक्ट के तहत तो इनको सिर्फ आपदा में यूज किया जा सकता है और इस बहाने से इन्होंने एलजी साहब ने रेवेन्यु सेकेट्री के माध्यम से इनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया। बीजेपी के इशारों पर। अब स्पीकर साहब मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ अगर ये योजना अवैध थी तो सात साल कैसे चल गई। इसी सदन से हर साल बजट भी पास

हुआ और अगर वैध है तो आप क्यो बहाना मार रहे हैं कि इसको तो कैविनेट की मंजूरी चाहिए। इसको तो कैविनेट से पास होना चाहिए। अगर ये अवैध है तो आप उनके ऊपर क्यो नहीं कार्यवाही कर रहे सात साल तक जिन अफसरों ने बजट पास किया और वैध है तो उसको फिर आप लागू क्यों नहीं होने देते। स्पीकर साहब ये नाम तो बार-बार राम का लेते हैं और राम के नाम सहारे सारे ऐसे काम करते हैं जो राम जी को पसंद नहीं आते होंगे। मैं दो लाइने बोल के अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ,

''कितनी दिक्कत होगी पता है राम समझ आ जाये तो।
राम-राम तो कह लोगे, पर राम-सा दुख भी सहना होगा।
पहली चुनौती ये है कि मर्यादा में रहना होगा
और मर्यादा में रहने का मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है
बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार को जलाना है।
अब रामलला के खातिर क्या इतना भी ना कर पाओगे।
अरे सबरी के झूठे बेर खाओगे तभी तो पुरूषोत्तम कहलाओगे।''

अध्यक्ष जी भाजपा का ये अहंकार इस देश को बर्बाद कर चुका है। चुनी हुई सरकार के खिलाफ काम ना करने देने की इनकी आदत देश का भट्टा बिठा रही है तो भाजपा वालों को परमात्मा सद्‌बुद्धि दे। दिल्ली के सिविल डिफेंस वॉलिंटियर्स की सर्विस जो उन्होंने रोकी है वो

बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने गंभीर चर्चा करने का मुझे अवसर दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैक्यु वेरी मच।

माननीय अध्यक्षः श्री अजय दत्त जी 5 मिनट में बोलेंगे।

श्री दिलीप पांडेः अध्यक्ष महोदय मेरा एक।

माननीय अध्यक्षः एक सेकेण्ड हाँ।

श्री दिलीप पांडेः इस महत्वपूर्ण विषय पे एक बहुत जरूरी प्रस्ताव है, एक संकल्प है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा आपके माध्यम से।

माननीय अध्यक्षः रखिए, बैठिए अजय दत्त जी।

श्री दिलीप पांडेः अध्यक्ष महोदय कल के बाद आज भी लगभग इसी विषय पर सदन पटल पर बहुत गंभीर चर्चा हुई है। दिल्ली की महिलाओं के मान सम्मान से उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये बहुत महत्वपूर्ण मसला है। जिस पर मैं एक संकल्प सदन के पटल पे प्रस्तुत करना चाहूंगा। आपकी अनुमति से। अध्यक्ष महोदय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा दिनांक 29 फरवरी, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में संकल्प करती है कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली इस महान सदन के संज्ञान में यह रहा है कि किस प्रकार से दशकों से महिलायें डीटीसी की बसों में उत्पीड़न और पूरे बर्ताव का शिकार होती रहती थीं और इन बसों में सफर करने में सुरक्षित महसूस नहीं करती थीं। इसके दृष्टिगत दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविन्द

केजरीवाल जी ने वर्ष 2015 से दिल्ली परिवहन निगम की बसों में मार्शलों को तैनात करके महिलाओं के लिए यात्रा को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाया। जिसके लिए यह सदन उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। मार्शलों की तैनाती होने से बसों में बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों के साथ होने वाली हिंसा, अपराध और अपमानजनक हरकतों पर रोक लग गई। दिल्ली परिवहन निगम और कलस्टर बसों में तैनात किये गए इन 8 हजार से भी ज्यादा मार्शलों में से लगभग 4 हजार होमगार्ड्स, 3600 सिविल डिफेंस वॉलिंटियर्स और लगभग 400 पूर्व सैनिक थे आश्चर्यजनक रूप से जनवरी 2023 से ही वित्त विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारी सिविल डिफेंस वॉलिंटियर्स की बसों में तैनाती पर आपत्ति जताने लगे और अप्रैल 2023 से दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री और वित्त मंत्री के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद इन सिविल डिफेंस वॉलिंटियर्स के वेतन का भुगतान रोक दिया गया और परिवहन विभाग ने भी बस मार्शलों की तैनाती की जरूरत पर आपत्ति लगाना शुरू कर दिया। अध्यक्ष महोदय जबकि दिल्ली की सरकार के परिवहन मंत्री वित्त एवं राजस्व मंत्री ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिविल डिफेंस वॉलिंटियर्स को बसों में बस मार्शल के रूप में तैनात करने के बिल्कुल साफ स्पष्ट निर्देश दिये थे। दिल्ली सरकार के दोनों मंत्रियों के निर्देशों के बावजूद राजस्व विभाग ने 1 नवम्बर, 2023 को आदेश जारी कर बसों में तैनात सभी सिविल डिफेंस वॉलिंटियर्स को हटा दिया। माननीय उपराज्यपाल महोदय ने भी इन मार्शलों की बहाली को मंजूरी देने से मना कर दिया। परिणाम स्वरूप बस मार्शल के रूप में काम करने वाले

हजारों सिविल डिफेंस वॉलिंटियर्स अब बेरोजगार हो गए हैं और बसों में यात्रा करने वाली महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों को एक बार फिर से असुरक्षा और अपमान का सामना करना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में मैं इस सदन के पटल पर प्रस्तावित करता हूँ कि सिविल डिफेंस वॉलिंटियर को बस मार्शल के दोबारा तैनात किया जाए। दूसरा दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को ध्यान में रखते हुए माननीय उपराज्यपाल को इन बस मार्शलों की नियुक्ति की नीति को मंजूरी देनी चाहिए और संबंधित मंत्रियों के निर्देशों के अवहेलना करके बस मार्शलों को हटाने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए और तीसरा यह सदन यह भी प्रस्तावित करता है कि राजस्व मंत्री और परिवहन मंत्री को माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके सिविल डिफेंस वॉलिंटियर्स को बतौर बस मार्शल बहाल करने की मांग करनी चाहिए।

माननीय अध्यक्षः अजय दत्त जी 5 मिनट में, मैं 5 मिनट से एक मिनट ज्यादा नहीं दूंगा, ध्यान रखिए।

श्री अजय दत्तः ठीक है अध्यक्ष जी धन्यवाद आपने मुझे बहुत ही गंभीर विषय पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी सिविल डिफेंस के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनका अगर बैकग्राउंड देखें तो कोरोना काल में उन लोगों ने पूरी दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी-बड़ी सेवायें दीं जो कोई दे नहीं सकता। हमने पर्सनली देखा है लोगों के घर खाना पहुंचाने से लेके, राशन पहुंचाने से लेके, दवाइयां पहुंचाने से ले के सारे काम किये और इसी घटना में कई सारे सिविल डिफेंस के ऑफिसर शहीद

भी हुए और एक ऑफिसर मेरी विधान सभा में भी शहीद हुए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ उस शहीद सिविल डिफेंस ऑफिसर को एक करोड़ की धनराशि दी गई और जिसकी वजह से उनको सम्मान भी मिला। जब ये योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिविल डिफेंस के ऑफिसर्स को लगाने की बात की तो उसके पीछे मंशा थी सेवा की, क्योंकि सिविल डिफेंस के ऑफिसर सेवा भाव से काम करते हैं और नवम्बर के महीने में 23 नवम्बर, 2019 को 4200 सिविल डिफेंस के ऑफिसरों को ये सेवा करने का मौका दिया। बस के अंदर महिलाओं की सुरक्षा करने का मौका दिया। बस के अंदर सारी व्यवस्थायें सुनिश्चित रहें, कोई महिलाओं के साथ बदतमीजी ना करे, कोई जेब ना कटे ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करायी गई और अध्यक्ष जी मैं बताना चाहता हूँ सिविल डिफेंस के ऑफिसर जो बस के अंदर अपना कार्य कर रहे थे महिलाओं की सुविधाका कार्य कर रहे थे, उस समय ना सिर्फ ये महिलाओं की सुरक्षा का कार्य कर रहे थे उसके अलावा जो नीचे बस में जो लोग जाते हैं उनकी लाइन लगवाने से लेके और बस को पूरा कहीं से अगर टर्न लेना है ये सारे कार्य कर रहे थे। तो ऐसे सेवा कर्मियों को ये मोदी सरकार के कहने पे एलजी साहब के कहने पे इन अफसरों ने निकाल दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी वालों से तुमने दो करोड़ देश के अंदर नौकरियां देने की बात की थी आज तुम 4200 लोगों को नौकरी से निकाल रहे हो। मैं ये बात करना चाहता हूँ इस देश का युवा कहां जाये। मैं ये बात करना चाहता हूँ कि ये सर्विस देने वाले लोग जिन्होंने अपने प्राणों की रक्षा ना करके कोरोना

के समय दिल्ली के अंदर सुरक्षा प्रदान की ये लोग जो एक मेरे यहां पर भरतलाल जी बैठे हैं जो सिविल डिफेंस में काम करते थे और बस मार्शल का काम कर रहे थे। उन्होंने खुद एक बार बस के अंदर एक जेब कतरे को पकड़ा और जेब कतरे से वहां की महिला का पर्स भी बचाया और उससे झगड़ा तक हो गया लेकिन जेब कतरे को छोड़ा नहीं तो ऐसे बस मार्शलों को हम सैल्यूट करते हैं। ऐसे बस मार्शलों को हमें देश के अंदर और अच्छी ट्रेनिंग देके काम कराना चाहिए। इन्होंने बस आनन-फानन में किसी आदेश को पारित करके और इनको निकाल दिया और ये वो लोग हैं जो इस ये वो लोग हैं अध्यक्ष जी बस एक मिनट और लेके खत्म कर रहा हूँ। ये वो लोग हैं जो बस मार्शल के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा करते हैं और मुख्यमंत्री जी ने जो थ्री लेयर सिक्योरिटी जो बनाई है जिसमें कैमरा लगाया, पैनिक बटन लगाये और मार्शलों को तैनात करके महिला सुरक्षा प्रदान की जिससे कि निर्भया जैसे कांड दोबारा ना हो सकें। उसके बाद इन लोगों की रोजी-रोटी वहां से चलती थी। तो बीजेपी वालों तुमने इनकी रोजी-रोटी छीनी है। मैं सभी बस मार्शलों से कहना चाहता हूँ कि आज हम सब कह रहे हैं कि ये ऑफिसर जानबूझकर दिल्ली सरकार के कामों को रोक रहे हैं। आपकी रोजी-रोटी को रोक रहे हैं। इनके घर पे धरना दो। एलजी साहब से पूछने जाओ कि हमारी रोजी-रोटी क्यूं इन्होंने छीनी है और दिल्ली के अंदर आज चुनाव जब होने जायेंगे तो आप सब लोगों से कहना कि ये लोग हमारी रोजी-रोटी छीनते हैं। अरविन्द केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री साहब को काम करने नहीं देने चाहते ये बात आप सबको कहनी है

घर-घर जाके। हम आपके साथ थे, हैं और रहेंगे और आपकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो महिलाओं के लिए जो सेवा प्रदान की है बस में उनको सैल्यूट करते हैं और सैल्यूट करते हैं जो 4200 लोगों को नौकरी दी उनको भी सैल्यूट करते हैं। अध्यक्ष जी आपने मुझे इस गंभीर मुद्दे पर बोलने का मौका दिया धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्री राजेश ऋषि जी।

श्री राजेश ऋषिः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय आपके जनरैल भाई के द्वारा माननीय राज्यपाल द्वारा जो परिवहन निगम में बसों में जो हमारे मार्शल तैनात थे उनको हटाये जाने पर जो उन्होंने ध्यानार्षण प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका समर्थन करते हुए आगे अपनी बात रखना चाहता हूँ। अभी दिलीप भाई ने भी अपना संकल्प प्रस्तुत किया। जिसमें उन्होंने बताया कि लगभग 10 हजार जो हमारे मार्शल्स हैं वो आज हड़ताल पे बैठे हैं। आखिर कारण क्या हुआ? आज ये स्थिति है कि हमारे दिल्ली के अंदर महिला सुरक्षा को लेकर बहुत ही बुरी हालत हो चुकी है। आप थाने में चले जाइये थाने वाले कोई एफआईआर लिखने को तैयार नहीं होते। वो कहते हैं जब तक कोई वारदात नहीं होगी तब तक आप आना मत। ये हालात हैं, दिल्ली में महिला सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे नेता अरविन्द केजरीवाल जी ने महिला सुरक्षा के लिए बसों में मार्शल्स की तैनाती की क्योंकि हमने देखा कि डीटीसी की बसों में महिलायें जाना पसंद नहीं करतीं। क्योंकि वहां पर सुरक्षा की भावना नहीं है। छेड़ाखानी बहुत होती थी। जेबकतरे बहुत होते थे। जब से हमारे मंत्री जी ने मार्शल्स की तैनाती बसों में उसके बाद से ना तो वहां पे

जबकतरों की संख्या नजर आती है अंदर। ना ही वहां पर अब महिलाओं के साथ कोई छेड़ाखानी होती है तो ये उसके बाद वहां कैमरे भी लगाये गये और साथ में पैनिक बटन लगाया गया ताकि कहीं और भी ऐसी कोई स्थिति हो तो उसमें हम लोग महिलाओं की सुरक्षा और तरीके से कर सकें। सबसे बड़ी बात ये है कि निर्भया कांड हमने देखा। निर्भया के समय जब बस के अंदर इतना बड़ा कांड हुआ उसको लेकर पूरे दिल्ली के अंदर तहलका मचा। लोग जागरूक हुए। सड़कों पर उतरे महिला सुरक्षा को लेकर। लेकिन हमारी सरकार जब आई तो सबसे पहला हमारा मुद्दा था महिलाओं को सुरक्षा देना। इसके लिए अरविन्द केजरीवाल जी ने सीसीटीवी कैमरे भी लगवाये। जगह-जगह पर हमने सीसीटीवी कैमरे लगाये हैं। साथ में बसों में मार्शल्स नियुक्त हुए। सर मार्शल्स की हमने देखा कि हमारे यहां मार्शल्स जो हैं आर्मी के लोग हैं रिटायर्ड। हमारे सिविल डिफेंस के लोग हैं। सिविल डिफेंस की जितनी भी हमारी टीम लगी हुई है। इन लोगों ने कोरोना में जो काम करके दिखाया वो कोई भूल नहीं सकता। उन्होंने जान को हथेली पर रखकर कोरोना में घर-घर खाना पहुंचाना, दवाइयां लेके पहुंचना सारे कार्य किये। मैं ये देख के हैरान था कि इतनी मेहनत करने वाले मार्शल्स जो हमारे यहां बसों के अंदर हम देखते थे कि जगह-जगह खड़े हो जाते थे, महिलाओं को उतारते थे उनको हटा दिया गया। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आपसे ये ही कहना चाहूंगा कि ये जो हमारे 10 हजार सिविल डिफेंस के और आर्मी के वर्कर जो काम कर रहे हैं इनको बहाल किया जाए। बीजेपी वालों को लगता है कि इन्होंने 10 हजार आदमियों

को नौकरी दे दी। इनके साथ इनके परिवार के लोग जुड़े हुए हैं। लगभग एक घर में चार आदमी भी जोड़े तो इस 5-5 वोट हैं। यानि लगभग 40 से 50 हजार वोटर हैं। इनके डर ये ही है इनके अंदर इनको हटाया जाए और नहीं तो ये जितने वर्कर काम कर रहे हैं हमारे सिविल डिफेंस के और सारे लोग जो मार्शल्स के तौर पे ये कहीं ऐसे ना हो इनके कार्यकर्ता बन जायें, इनके साथ हो जायें। क्योंकि आप जब किसी का अच्छा करते हैं तो आपके लिए अच्छा करने के लिए तैयार रहते हैं। ये जो हमारे एलजी साहब के जितने भी बैठे अधिकारी हैं उन्होंने किस तरीके से इन्हें हटाया हर कोई जानता है। सर मेरे यहां पर एक बहुत बड़ी टीम इक्ट्ठी होकर मेरे ऑफिस में आई। ऑफिस में आने के बाद उन्होंने मुझे एक ज्ञापन दिया तो मैंने जब ज्ञापन पड़ा तो उसके अंदर सारा पॉलिटिकल मैटर नजर आया। मैंने उनसे कहा कि एक चीज बताइये आपको जब नौकरी मिली एक तरीके से नौकरी के तौर पे आप लोग रहे। आपको तन्ख्वहा भी मिली। जब तक मिलती रही तब तक आपने कुछ नहीं कहा। जब आपको मिलना बंद हुआ और आप ये भी जानते हैं कि किन लोगों ने आपको हटाया है। वो बोले कि हमें मालूम है। मैंने कहा इसके बाद अगर मालूम है तो आप एलजी ऑफिस के सामने धरना दो ना। क्यों देते हो आप वहां जाकर। सेकट्रेट के सामने आप धरना दे रहे हैं तो उन लोगों की समझ में आया कि हम पॉलिटिकल दबाव में फंसे हुए हैं। बीजेपी के लोगों के बीच में फंस गए हैं अब वो धीरे-धीरे निकल रहे हैं और मैं आज माननीय अध्यक्ष जी मेरा आपके माध्यम से एलजी साहब से भी अनुरोध है कि वो इन

सब लोगों को वापस इनकी जॉब पे रखे और मैं इन डिफेंस वॉलिंटियर्स से भी कहना चाहूंगा कि आप अपनी आंखें खोलिए और राजनीतिक दवाब में ना आयें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: प्रमिला जी।

श्रीमती प्रमिला धीरज टोकस: धन्यवाद अध्यक्ष जी आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी सबसे पहले तो मैं सैल्यूट करती हूँ मार्शलों को और सिविल डिफेंस के जो कार्यकर्ता हैं उन सभी को। क्योंकि जब इतनी भयंकर महामारी थी। जब हमारे परिवार के सदस्य भी आपस में नहीं मिलते थे, नहीं बात करते थे। जब इन्होंने वो सेवायें दी हैं और मुझे लगता है कि जब भाजपा ने एयरपोर्ट बेच दिया, रेल बेच दी मुझे लगता है इन्होंने शर्म भी बेच खाई है अपनी। क्योंकि यहां पे अभी हमारे बिधूड़ी साहब जी इसी सदन में अभी इन्होंने बोला था कि केजरीवाल जी ने बोला था कि हम नौकरियां देंगे। नौकरियां दे रहे हैं तो ये छोड़ते नहीं हैं। इन्होंने कहा कि हम 80 करोड़ लोगों को 4 किलो अनाज और 1 किलो चावल देते हैं हम। इनको वो खैर बेच ही खाई है शर्म तो है ही नहीं और लगता है कि भाजपा वालों ने झूठ बोलने में पीएचडी कर रखी है। सभी ने मुझे लगता है कि सच्चाई भी इन्होंने बेच दी है। सच तो इन्होंने बोलना ही नहीं है। ये दो चीज इनके पास थी ये तो खरीदने के बाद भी नहीं इनको मिलेगी अब और जिस प्रकार से ये बोलते हैं कि हम 80 करोड़ मुझे लगता है कि ऐसा चलता रहा 80 करोड़ से लेके क्योंकि जो

हमारा राजा है, जो हमारे देश का जो राजा होता है या उनको पिता कहें उनके 5-6 ही राजा पुत्र हैं जो उनके लिए वो काम करते हैं। औरों को तो उन्होंने भिखारी ही बनाना है, कटोरा ही देना है हाथ में। और अध्यक्ष जी मैं तो ये मांग करती हूँ जितने भी भाजपा के लोग हैं उन सभी के घरों में 4 किलों गेहूं और 1 किलो अनाज दें वो मुझे दिखायें कि वो पूरा महीना कैसे निकालेंगे उसमें। और जिस प्रकार से श्री अरविन्द केजरीवाल जी बसों में मार्शल लगाये अध्यक्ष जी वो खाली महिलाओं के लिए नहीं है जो बुजुर्ग हैं, जो असहाय हैं उनके लिए भी हैल्प करते हैं, उनकी भी मदद करते हैं और ये इतना अवैध था कि 2015 से और 22 तक इन्होंने वेतन दिया और अब कह रहे हैं कि वेतन नहीं देंगे। ये इतना अवैध था तो अब से 15 से 22 तक इन्होंने कैसे उनको वेतन दिया और अब कैसे ये गलत हो गया। मेरी अध्यक्ष जी यही मांग है कि जिन अधिकारियों ने ये अभी इनका वेतन रोका है मार्शलों का और सिविल डिफेंस के वॉलिंटियर्सों का मैं आपसे मांग करती हूँ कि उनको जो भाई दिलीप पांडे जी ने संकल्प किया है मैं इसका समर्थन करती हूँ और जो ऐसे अधिकारी हैं उनपे सख्त कार्यवाही की जाए और जो मार्शल और सिविल डिफेंस के जो दस हजार बच्चे, हमारे छोटे बहन भाई बैठे हैं, उनको जल्द से जल्द वापिस उनकी नौकरी दी जाए ताकि वो अपना घर खर्च चला सके। मैं बस इतना ही आपसे निवेदन करती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्रीमान कैलाश गहलौत जी, माननीय मंत्री। मेरे पास स्लिप नहीं आई है। बिधूड़ी जी।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के माननीय सदस्य सरदार जरनैल सिंह जी के द्वारा नियम 54 के तहत सिविल डिफेंस वालंटियर्स या ये कहिए कि बस मार्शल्स का मामला उठाया है। सिविल डिफेंस वालंटियर्स की बहाली हो, मैं इसके पक्ष मे हूं। भाजपा विधायक दल ने अपनी राय उनके पक्ष में व्यक्त की है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, लंबे समय से ये मार्शल्स दिल्ली सरकार के सैक्रेट्रियेट पर धरना लगा कर बैठे हैं। मुझे ये जानकारी भी मिली है कुछ मार्शल्स की मृत्यु हो गई, उनके परिवार बहुत संकट में हैं। लेकिन मैं आज आपके माध्यम से दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी से ये जरूर जानना चाहता हूं कि सरकार के एक लंबा समय मिला इनको नियमित करने का और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के मैंने अनेक वीडियो, इनके स्टेटमेंट्स उनके पक्ष में देखे हैं उनको नियमित करने का वायदा दिल्ली के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के द्वारा किया गया। आखिर इतना लंबा समय क्यूं लगा। उनकी भर्ती के बाद उनको नियमित किया जाना था। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं यहां कोई आरोप-प्रत्यारोप करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं, इसका समाधान कैसे निकले इस पे चर्चा करके कोई रास्ता निकले, मैं उस पक्ष का हूं। अब ये जानकारी भी दी गई है, वह ठीक है या गलत है, ये दिल्ली सरकार ने ये स्वीकार कर लिया और फाईल पर नोटिंग है इनकी जो भर्ती हई उसमें नियमों का पालन नहीं हुआ। इस पर सरकार का क्या स्टैण्ड है। दिल्ली सरकार के अनेक विभाग हैं, क्लास फोर की हजारों नौकरियां खाली पड़ी हैं, ये सदन इस बात के

लिए प्रस्ताव पास करे कि यदि किन्हीं कारणों से उनकी भर्ती नियमों का उल्लंघन करके मान लो मुझे नहीं मालूम कि ऐसा हुआ है। यदि है अब वो कहीं दूसरी जगह उनको कोई नौकरी मिल नहीं सकती बहुत उम्र भी हो गई है तो दिल्ली सरकार के जो अनेक विभाग हैं उसमें हजारों क्लास फोर की नौकरियां खाली पड़ी हैं इन सभी सिविल डिफेंस वालंटियर्स को, मार्शल्स को सरकार उन विभागों में नौकरी दे ये मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से मांग करना चाहता हूं और जरूर क्योंकि ये लोगों में इस बात का प्रचार किया जा रहा है और जो हमारे मार्शल्स हैं उनके द्वारा किया जा रहा है कि यदि सरकार ने ठीक से स्टैंड लिया होता तो उनको नौकरी से नहीं निकाला जाता। क्या कारण रहे हैं कि सरकार को फाईल पर ये नोटिंग देनी पड़ी कि नियमों का उल्लंघन करके इनकी भर्ती हुई है। मैं जरूर आदरणीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा और उनकी बहाली हो मैं इसका जोरदार तरीके से समर्थन करता हूं उसके लिए कहीं तक भी जाना पड़ेगा, हम उसके लिए जाएंगे, उनके साथ न्याय हो, बहुत ही उनकी जो स्थिति है मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूं, बहुत दुखद है। तो इसका कोई रास्ता मिल बैठकर निकालना चाहिए, क्या रास्ता हो सकता है मैं उस हक का आदमी हूं मुझे आपने समय दिया बहुत बहुत आभारी आपका और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से एक बार फिर आग्रह करते हुए कि इस समस्या का समाधान करना चाहिए क्योंकि दिल्ली में इलेक्टिड गवर्नमेंट है और दिल्ली के लोग या दिल्ली के मार्शल्स, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से ही ये उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि वो निश्चित तौर पर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः माननीय मंत्री जी। कैलाश गहलौत जी।

माननीय परिवहन मंत्री (श्री कैलाश गहलौत): अध्यक्ष जी बहुत ही गंभीर विषय इस सदन में है और काफी माननीय विधायकों ने चर्चा की और अभी जो दिलीप भाई का संकल्प है मैं बिल्कुल उसका समर्थन करता हूं। अध्यक्ष जी, एक चीज मुझे समझ में नहीं आती 2015 से लगातार बस मार्शल्स बसों में तैनात थे और उसके पीछे भी मैं ज्यादा विस्तार में नहीं बात करूंगा क्योंकि काफी चर्चा हो चुकी है इस इशु पे लेकिन कहीं ना कहीं मकसद सिर्फ इतना था कि जो यात्री हैं और स्पेशली जो फीमेल पैसेंजर्स हैं और बसों में जो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, सुरक्षा का जो मामला है और माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी का जो विज़न था कि बसों में जब हमारी महिलायें सफर करें तो उनको ऐसा लगे कि जैसे वो अपने घर में हैं। उनका कोई परिवार का एक सदस्य है, कोई भाई है, कोई बेटा है, कोई बहन है जो उनकी सुरक्षा के बारे में और ये चीज जब सीएम साहब खुद बसों में महिलाओं के बीच जब गए थे बसों में तो महिलाओं ने खुद कहा ये चीज और मैं साथ में था कि जी हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी सुरक्षा के लिए कोई हमारा अपना है जोकि वर्दी में भी है। ये सोच सिर्फ इतनी थी और पूरी दुनिया मैं रिकार्ड पे कह रहा हूं कि पूरी दुनिया में चाहे वो इस देश की सबसे बड़ी सरकार हो, सबसे बड़ी पार्टी हो और चाहे दुनिया में कोई और जितने डवलप्ड नेशंस हों, किसी कि इतनी हिम्मत नहीं थी कि जो इतने बड़े पैमाने पे, इतने बड़े स्केल पे इस तरह की स्कीम को लांच किया जाए। महिलाओं का सफर जो

है वो किस प्रकार से सुरक्षित किया जाए तो 2015 से फिर महिलाओं का सफर फ्री हुआ। 2019 में तो सीएम साहब का निर्णय था कि भई सभी बसों में मार्शल्स तैनात किए जाएं। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी मैं था, रेवेन्यू मिनिस्टर भी मैं था। ये जो बार बार ये बीजेपी वाले कहते घूम रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी के वालंटियर्स हैं मैं उसको क्लैरिफाई करना चाह रहा हूं। डीजी होमगाड्र्स को बुलाया गया कि भई आप इतने होमगाड्र्स हमें दे दें 14 हजार, बार बार उनसे मीटिंग की गई, बार बार एडवर्टिजमेंट इशु किए गए, डीजी होमगार्ड ने हाथ खड़े कर दिए कि जी हम इतने होमगार्ड नहीं दे सकते। हमने दोबारा पूछा बोले जी बिल्कुल नहीं दे सकते होमगार्ड। हम तीन-चार हजार से ज्यादा होमगार्ड नहीं दे सकते। उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट को क्योंकि वो डिजास्टर से कम नहीं है ये चीज अगर अगर किसी शहर में अगर महिलायें सुरक्षित नहीं हैं, अगर पैसेंजर सुरक्षित नहीं हैं तो डिजास्टर का मतलब ये नहीं है कि कहीं आग लग गई, कहीं earthquake आ गया। ये भी एक तरह का डिजास्टर है और जब उस टाईम रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी थे उन्होंने फाईल पे इस चीज को माना तभी हमें सिविल डिफेंस वालंटियर्स दिए। उसका बैकग्राउंड ये है कौन कह रहा है कि बस मार्शल्स की नियुक्ति में इल्लिगल चीजें हुई हैं आप बताइए? बिधूड़ी जी इतने रिसपांसिबल, अभी कह रहे थे मैं बड़ा सीनियर हूं। हम कह रहे हैं सीनियर हैं, हम आपका आदर करते हैं, लीडर आफ ओपोजिशन हैं वो अलग बात है। आजकल थोड़ा भावुक हो के किसी की बड़ाई करने के मामले में कुछ गलत चीजें कह जाते हैं लेकिन

कहां हैं, अच्छा ये कह रहे हैं कि जी हमने अप्वाइंट कर दिए बस मार्शल्स, अधिकारियों की नोटिंग है कि जितने भी बस मार्शल्स हैं और कोई सैन्ट्रलाइज तरीके से भी बस मार्शल्स की रिक्रूटमेंट नहीं हुई है और बकायदा उनके पैरामीटर्स थे, बकायदा उनके पैरामीटर्स थे बस मार्शल्स के ऐसा नहीं है कि कोई भी आया और उसको ले लिया गया। उनके बकायदा पैरामीटर्स थे बस मार्शल्स के कि भई हाइट इतनी होगी 165 सैंटीमीटर मेल की, 150 सैंटीमीटर फीमेल की है। कम से कम आठवीं क्लास वो पास होने चाहियें। अपर एज लिमिट 50, ये मैडिकल सर्टिफिकेट होगा। मिनिमम वन इयर की ऐसी कंडीशन होगी विमेन कैंडीडेट्स भी अप्लाई किए जाएंगे तो ये सारी चीजें फाईल में, उसके बाद डिसैंट्रलाइज तरीके से इनका सलैक्शन हुआ। ग्यारह-बारह डीएम जो हैं उन्होंने बकायदा कमेटी बनी, उसमें उनका सलैक्शन हुआ। तो कौन कह रहा है कि भई ये सारे आम आदमी पार्टी के वालंटियर्स हैं। ये सिर्फ बहाने हैं। उनको कोई ना कोई रास्ता निकालना था कि किस प्रकार से एक जो स्कीम अरविंद केजरीवाल जी लांच की और ये तो बार बार हम कह रहे हैं कि बीजेपी वाले जो हैं वो उनको महिला सुरक्षा से कोई मतलब है, नहीं। ये बिधूड़ी जी कह रहे थे अभी कि जी वहां पर सचिवालय में धरने पे बैठे हैं तो भई आप लोगों ने क्या किया? अगर ये कह रहे हैं कि ये उनके साथ हैं तो इन्होंने क्या किया। कह रहे हैं कि बीजेपी विधायक दल उनके साथ है। ये अध्यक्ष जी सरासर राजनीति हो रही है और घटिया राजनीति है। बस मार्शल जो बनना चाहता है वो कोई संपन्न परिवार से नहीं है, ना उसके पास कोई

अच्छी नौकरी है, तब जाकर वो अच्छा ये परमानेंट नौकरी भी नहीं है उनको तो पर दिन का, हर दिन का ऑनरेरियम मिलता है तो बस मार्शल कौन बनना चाहेगा जो बेचारा गरीब परिवार से है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। रूरल एरिया से मोस्टली मैं तो खुद ऐसी विधानसभा से आता हूं। कल मैं तीन गांव गया अध्यक्ष जी कंझावला, निजामपुर, सावदा, आप यकीन कीजिए मैं बिल्कुल सच बता रहा हूं आपको, वहां भी बस मार्शल जो हैं जब उनको पता चला कि परिवहन मंत्री यहां पर आ रहे हैं वहां भी मेरे सामने बस मार्शल.. और मुझे वाकई में मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। मतलब क्या बोलें इनको, एक व्यवस्था जो जिससे कि दोनों तीनों चीजें हो रही हैं, पैसेंजर्स को सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। हमारे जो नौजवान साथी हैं उनको नौकरी मिल रही है, उनके भी दुश्मन बन गए और बिधूड़ी जी को मैं इनका इतना रिगार्ड करता हूं। पर पता नहीं इनके उपर क्या दबाव है, ये बार बार खड़े हो के केवल राजनीति कर रहे हैं। अभी कह रहे थे, सर्कल रेट की बात कर रहे थे भई किसने भेजी सर्कल रेट की फाईल वापिस दो बार। कह रहे हैं जी मैं किसान का बेटा हूं। कौन से किसान के बेटे हैं, भई दो बार हम फाईल भेज चुके हैं। अध्यक्ष जी, दो चीजे हैं या तो ये बहुत वो हैं या बहुत समझदार हैं। अब वो हैं नहीं लेकिन जनता बेवकूफ नहीं है मैं इतना ही आपको कहना चाहूंगा। ये इतने सीनियर लीडर हैं और मुझे लगता है कि एलजी साहब टाईम भी नहीं देते इनको क्योंकि अगर टाईम देते होते तो ये जा के बोलते, कह रहे हैं सर्कल रेट कौन करेगा सर्कल के रेट। दो बार हम फाईल भेज चुके हैं बना बना के पहले इन

अफसरों की बात करो। अच्छा एक चीज और बताइए मुझे एज़ ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, एज ए रेवेन्यू मिनिस्टर इनक्ल्यूडिंग फाइनेंस मिनिस्टर की ज्वाईट मीटिंग में डिविजनल कमिश्नर के सामने प्रिंसिपल सैक्रेट्री फाइनेंस के सामने सैक्रेट्री होम के सामने हमने आदेश दे दिए कि भई जब तक अगर आप ये चाहते हैं कि अगर ये इन बस मार्शल का काम नहीं हैं तो जब तक इसका कोई ऑल्टरनेट अरेंजमेंट, कह रहे थे कि जी, तो कैबिनेट नोट किसको पुटअप करना था। अगर ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर इनको रेगुलराईज नहीं किया गया पहले बताओ किस चीज का रेगुलराईज करना था। बस मार्शल्स काम कर रहे हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने सहमति दी हुई है। बस मार्शल की रिक्रूटमेंटमेंट कहां से हुई, उनके कोई अलग से थोड़ी रिक्रूटमेंट हुई। सिविल डिफेंस वालंटियर्स जो लगातार निष्काम सेवा मतलब बिना किसी लालच के उन्होंने कई साल जो हैं वो अपनी सेवाएं दी, वही लोग सिविल डिफेंस वालंटियर्स बस मार्शल हैं आप देखिए पूरी दिल्ली में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है चाहे वो कोविड का समय हो, चाहे वो ओड ईवन का समय हो, माननीय सीएम साहब भी बोलेंगे मैं उसमें नहीं जा रहा कि कितने बस मार्शल ने कितना बढ़िया काम किया। सीएम साहब ने खुद उनको आ के उनकी पीठ थपथपाई, किडनैपिंग से ले के और जितने भी चीजें हैं। तो मिनिस्टर्स के डायरेक्शन के बावजूद लगातार और मेरे पास जितनी बार भी फाईल आई एज ए रेवेन्यू मिनिस्टर, एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मैंने बार बार क्लियरली ये लिखा है कि भई आप ये कह रहे हो कि सीसीटीवी पैनिक बटन आप ये बताईये कि एक बच्ची

का किडनैप हो रहा है उसमें सीसीटीवी क्या करेगा। वो तो बाद की बात है कि इंवेस्टीगेशन के टाईम पुलिस जो है उसको यूज करेगी। अच्छा सीसीटीवी भी ये कह रहे हैं महिलायें, महिलायें सुरक्षा निर्भया फंड से एक पैसा नहीं दिया दिल्ली सरकार को not even a single penny. पहले कहते हैं हम सरकार को पैसा देंगे लेकिन माननीय सीएम साहब की सोच और उनका दिल मुझे आज भी वो याद है कि मैंने सीएम साहब को कहा जा के कि जी निर्भया फंड से एक पैसा नहीं मिलेगा ये जो सीसीटीवी और पैनिक बटन हम लगाना चाह रहे हैं इस पर 200 ढाई सौ करोड़ रूपये का खर्चा है मेरे वो चीज कानों में गूंज रही है कि कैलाश आप चिंता मत करो ये हमारी कमिटमेंट में है। मेरी कमिटमेंट है दिल्ली वासियों की कि जो हमारी महिलायें और ये भी बताना चाहूंगा पूरे देश में ये बार बार कहते रहते हैं डीटीसी घाटे में चली गई, डीटीसी घाटे में चली गई हम ये तो कभी नहीं कहते कि स्कूल घाटे में चले गए। हमने कहा है भई हॉस्पिटल घाटे में चले गए तो कौन से घाटे में चले गए। सरकार का फैसला है कि हम किराया नहीं बढ़ाएंगे, हम लोगों को पॉल्यूशन को माइंड में रखते हुए एनकरेज कर रहे हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चले। वो बार बार उसमें चले जाते हैं ये तो कभी नहीं कहेंगे पूरे देश में केवल एक सरकार है जिसकी जितनी भी बसें हैं और ये अरविंद केजरीवाल का जो मॉडल है उसको एक चेहरा है हर बस में सीसीटीवी है, पैनिक बटन है, जीपीएस है और ये भी सारी महिला सुरक्षा को देखते हुए है, तो वो चीज तो कभी नहीं कहेंगे। तो अध्यक्ष जी मेरे ख्याल से इन्होंने एक

और भी इश्यू उठायालाल डोरा। एज ए रेवेन्यू मिनिस्टर मेरे आदेश है फाईल पे और एक बार नहीं कम से कम तीन बार ये आदेश दिए कि भई लालडोरा बढाया जाए। अफसरों ने क्या कहा कि जी ये तो जमीन से मामला जुड़ा हुआ मामला है, ये तो एलजी साहब के अधिकार क्षेत्र में है। तो कौन काम रोक रहा है? कह रहे हैं जी मैं किसान का बेटा हूं बिधूड़ी जी बार बार खड़े हो के कह देते हैं। भई सिर्फ कहने से नहीं होगा अगर आप वाकई में किसानों के हित की बात करते हैं तो फिर जा के एलजी साहब से मिलिए और ये पूछिए कि उन्होंने फाईल दो बार क्यों लौटाई, उनसे पूछें की सर्कल रेट आपने क्यों नहीं बढ़ाए। अब ये एक चीज कही इन्होंने alternate plot किसने देने हैं। alternate plot वो तो लैंड एंड बिल्डिंग का डिपार्टमेंट है जिन्होंने देने हैं। वो भी एलजी साहब को करने हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता ये बार बार खड़े हो के ये कहते रहते हैं कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, भई सारे काम तीन काम आपने कहे तीनों काम और चौथा बस मार्शल्स का। बस मार्शल्स किसलिए हटाए, मुझे कोई संकोच नहीं है इस पूरे सदन के बीच ये कहने में कि बस मार्शल्स को हटाने के पीछे बहुत बड़ी साजिश है और बीजेपी के तहत ये साजिश हुई है। इसमें कोई संकोच नहीं है कहने के लिए। अध्यक्ष जी मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बस मार्शल के साथ पूरी सरकार, ये पूरा सदन और केवल सदन नहीं, नहीं, पूरी दिल्ली की जनता उनके साथ है। उनका जो दुख है, उनका जो दर्द है मैं समझ सकता हूं कि केवल जो मेरे ख्याल से 15 से 16 हजार रूपये महीने के जो कमाता है उसका परिवार कैसे

चलता है वो मैं समझ सकता हूं और ये बहुत ही घटिया राजनीति इनके साथ की गई है लेकिन उनको ये भी मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि पूरी सरकार सीएम साहब जो हैं वो पूरे उनके साथ हैं और जब तक उनकी बहाली नहीं होगी, हम चैन से नहीं बैठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी।

माननीय मुख्यमंत्री (श्री अरविंद केजरीवाल): अध्यक्ष महोदय, जब हमारी 2015 में सरकार बनी थी तो हम इस वादे के साथ आए थे कि महिलाओं की सुरक्षा को ले के जो हमसे बन पड़ेगा, हम करेंगे। दिल्ली पुलिस हमारे पास नहीं है जोकि सीधे सीधे जनता की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। लेकिन हमारे दायरे में जो कुछ आता था हमने वो सब किया। हमने पूरी दिल्ली में इतने सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जोकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूयार्क, टोक्यो, फ्रांस, पेरिस सारे दुनिया में लंदन जितने सीसीटीवी कैमरे हमने लगाए हैं, पूरी दुनिया में उतने कहीं नहीं हैं और केवल पांच साल के अंदर लगा दिए इतने सीसीटीवी। जितने डार्क स्पॉट्स थे हमने वहां पे स्ट्रीट लाईट्स लगवाई और उसी दिशा में हमने बसों के अंदर बस मार्शल्स की नियुक्ति की। एक तरफ बसों के अंदर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए, पैनिक बटन भी लगाए गए और साथ साथ बस मार्शल्स की नियुक्ति भी की गई क्योंकि बसों के अंदर ना केवल महिलाओं की सुरक्षा का मामला छोटे मोटे कई सारे अपराध होते हैं। जेब कतरे आते हैं, जेब काटते हैं, छेड़छाड़ करते हैं,

महिलाओं के साथ किस्म किस्म के अपराध होते हैं उन सब अपराधों को रोकने के लिए बस मार्शल्स की नियुक्ति का प्रपोजल बनाया गया और 2015 से बस मार्शल्स अच्छा काम कर रहे थे। मेरे पास ढेरों उदाहरण हैं जो बस मार्शल्स ने शानदार काम किया है। 20, नवंबर 2019 को मार्शल अरूण कुमार ने देखा कि एक चार साल की बच्ची को ले के एक आदमी बस से नीचे उतर रहा है और वो बच्ची जोर जोर से रो रही है धौला कुआं के पास। तो उसे शक हुआ और उसने उस आदमी को पकड़ लिया और पता चला कि वो उस बच्ची का किडनैप करके लाया था निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से और बाद में बच्ची को अपने पैरेंट्स के साथ मिलवाया गया। 29 अक्टूबर, 2019 को मार्शल मनीष कुमार ने देखा कि एक आदमी ने टिकट नहीं ले रखी है और उसका suspicious behaviour था, उसे पकड़कर जब उसका बैग छानबीन की गई तो उसमें से 5 मोबाइल फोन और 4 एटीएम की मशीनें निकली, उसे भी थाने में हैंडओवर किया गया। नवंबर, 2019 में मार्शल संतोष ने एक चोर को रंगे हाथों पकड़ा और उसके यहां से एक चोरी किया हुआ मोबाइल फोन मिला 540 नंबर बस में। 6 जनवरी, 2023 को मार्शल संदीप चकारा ने एक आदमी को एक लड़की के साथ गलत काम करते हुए रोहिणी के क्षेत्र में पकड़ा और उस आदमी को, इस तरह के ढेरों एग्जाम्पल्स हैं, उसे पुलिस के हवाले किया गया।

ये स्कीम अच्छी खासी चल रही थी और अचानक इस स्कीम को एक नवंबर से बंद कर दिया गया। इसके पीछे का मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहता हूं कि स्कीम 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

22, आठ साल ये स्कीम चली। इसमें तीन विभाग शामिल हैं, एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लिखता है कि भई हमें इतने बस मार्शल चाहिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसके आधार पर सिविल डिफेंस वॉलन्टियर्स की भर्ती निकालता है और उनको रिक्रूटमेंट करता है और फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो उसकी पेमेंट करता है, तो तीन डिपार्टमेंट हैं। 2015 से 2022 तक ये तीनों डिपार्टमेंट, शांतिपूर्वक हर साल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट लिखता था हमें इतने बस मार्शल चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट उतने सिविल डिफेंस वॉलन्टियर्स की भर्ती करता था, कोई दिक्कत नहीं, फाइनेंस डिपार्टमेंट उनकी पेमेंट करता था, कोई दिक्कत नहीं।

2023 के शुरू से अचानक तीनों डिपार्टमेंट्स ने अपना रूख, अफसर वो ही थे, अफसर नहीं बदले, कई–कई वहां जो अफसर हैं वो तो तीन–तीन, चार–चार साल से मौजूद थे, अचानक उन्हीं अफसरों ने अपना लिखना बदलना चालू कर दिया, फाइल पर लिखना चालू कर दिया, सिविल डिफेंस वॉलन्टियर्स का ये काम नहीं है। सात साल, आठ साल तक था काम, अचानक उन तीनों ने, इन्होंने रेवेन्यू वालों ने भी और फाइनेंस वालों ने भी और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर तो अगस्त तक लिखता रहा कि भई मेरे को बस मार्शल दो, मेरे को बस मार्शल दो, इनकी पेमेंट करो, पुरानी पेमेंट करो, कई दिनों से तनख्वाह नहीं दे रखे। अगस्त में अचानक उस कमिश्नर– ट्रांसपोर्ट ने जोकि तीन–चार साल से था ये कमिश्नर– ट्रांसपोर्ट, आशीष कुंद्रा, आशीष कुंद्रा तीन–चार साल से कमिश्नर था, हर साल वो requisition करता आ रहा है। अचानक अगस्त, 2023

में क्या हो गया, एल.जी. साहब ने उनको, हमने पूछा अफसरों से क्या हो गया, एल.जी. साहब ने उनको बुलाया और उनको धमकाया कि अगर तुमने ये स्कीम बंद नहीं की तो तुमको सस्पेंड कर दूंगा, तुमको जेल भेज दूंगा, ईडी छोड़ दूंगा तुम्हारे पीछे, सीबीआई छोड़ दूंगा, तुमको जेल भेज दूंगा, ये इसके पीछे की कहानी है। अफसर रो रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो अफसर चार साल से requisition कर रहा था अचानक उसका एक दिन सपना आया और उसे सपने में सिविल डिफेंस वॉलन्टियर एक्ट दिखाई दिया और एक्ट में वो धारा दिखाई दी कि ये काम नहीं कर सकते, ऐसे थोड़े ही है, बेवकूफ बना रहे हो हमको, पूरी दुनिया बेवकूफ है। सारे देश के लोग बेवकूफ हैं, तुम ही सयाने हो। उनको बुला-बुलाकर धमकाया गया, ये स्कीम बंद करवाई गई, क्यूं? क्योंकि ये स्कीम महिलाओं के अंदर बहुत पापुलर थी। दिल्ली के बस में ट्रेवल करने वाले लोगों को ये, जैसे अभी कैलाश गहलोत ने, इन्होंने बताया कि उनको ये लगता था कि हमारा अपना आदमी वर्दी में बैठा है, ये हमारी सुरक्षा करेगा, और इस तरह से ये स्कीम बंद करवाई गई।

अध्यक्ष महोदय, मैं, मेरे को जब पता चला और सिंतबर में, अगस्त और सितंबर में मैंने कागज देखे हैं, मंत्री जी ने, रेवेन्यू मिनिस्टर ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने अधिकारियों के साथ मीटिंग्स ली, मिनट्स ऑफ मीटिंग है, मिनट्स ऑफ मीटिंग में कहा गया कि ये स्कीम बंद नहीं होनी चाहिए। लिखित में आदेश दिए गए कि ये स्कीम बंद, लेकिन

एल.जी. से तो सारे ही डरते हैं, xxxxxxxx[3] एल.जी. तो किसी को भी सस्पेंड कर सकता है, बड़ा पावरुल आदमी है, किसी को भी कुछ भी कर दें, तो एल.जी. से सारे डरते हैं।

जब मेरे को पता चला मैं एल.जी. साहब से मिलने गया। मैंने कहा सर ये क्या हो रहा है, मैं सुन रहा हूं कि आप सिविल डिफेंस वॉलन्टियर्स को और इनको हटाने की वो कर रहे हों तो उन्होंने कहा कि अरविंद जी देखो अब बसों के अंदर तो सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं और ये पैनिक बटन भी है, क्या जरूरत है बस मार्शल्स की, हम 280 करोड़ रुपये इनके ऊपर खर्च कर रहे हैं। मैंने कहा सर मेरे लोग हैं दिल्ली के दो करोड़ लोग, मैं 280 तो क्या 2080 भी करूंगा खर्च, मेरी मर्जी। मेरे को लोगों ने चुनकर भेजा है, आपको तो चुनकर नहीं भेजा, मेरे को लोगों ने चुनकर भेजा है, मैं अपने लोगों की सुरक्षा के लिए 280 क्या 2800 करोड़ रुपये खर्च करूंगा, आप कौन होते हैं इसको रोकने वाले, आप तो नहीं रोक सकते। और मैंने कहा अगर सीसीटीवी कैमरे और पैनिक बटन से ही हो जाता तो मैंने कहा सारे राज निवास के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे तो लगे हुए हैं, पैनिक बटन और दीवारों पर लगा देते हैं, आपकी सुरक्षा हटा देते हैं, क्या जरूरत है आपकी सुरक्षा की। पूरी दिल्ली के अंदर तो सीसीटीवी कैमरे लगा ही दिए, पैनिक बटन और लगा देते हैं हर खंबे के ऊपर, दिल्ली पुलिस भंग कर देते हैं, क्या जरूरत है। अरे लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी होती है किसी भी समाज के अंदर सुरक्षा की। एक लेयर ऑफ

[3] चिन्हित अंश अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदन की कार्यवाही से निकाले गए।

सिक्योरिटी बसों के अंदर है सीसीटीवी कैमरे की, एक लेयर ऑफ है पैनिक बटन की, एक है बस मार्शल की। कोई किसी के सामने पैनिक बटन आया और उसको ध्यान आ गया वो पैनिक बटन दबा देगा, बाद में अगर अपराध को जांच करने के लिए सीसीटीवी कैमरे की जरूरत पड़ी, सीसीटीवी कैमरा, बस मार्शल किसी के सामने बैठा हो और कोई लड़की को छेड़ रहा है, वो बस मार्शल को कहेगी भैया इसको जरा सा रोको। हम लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी तो उसको रोका कैसे जा सकता है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं नहीं रूकने दूंगा। और फिर उन्होंने फाइल के ऊपर आदेश कर दिया कि इनको हटा दिया जाए। जिस दिन ये अखबार के अंदर छपा था मैंने, मेरे को याद है जिस दिन उन्होंने ये आदेश किया था, दो दिन पहले अखबार के अंदर छप गया था कि एल.जी. साहब रोकने वाले हैं। मैंने फोन किया एल.जी. को, सवेरे-सवेरे उठकर 8 बजे मैंने फोन किया, सर ये अखबारों में मैं क्या पढ़ रहा हूं, आपने मेरे को प्रॉमिस किया था कि आप इनको नहीं हटाओगे, आप क्यूं हटा रहे हों इनको। मैंने उसी दिन चिट्ठी लिखी, मैं कहीं और गया हुआ था उस दिन, मैंने वहां से चिट्ठी लिखी एल.जी. साहब को कि, और वो चिट्ठी तीन, एक चिट्ठी लिखी और दो बार नोट भेजा है मैंने, एक मंत्री के थ्रू नोट भेजा कि मौजूदा सिविल डिफेंस वॉलन्टियर्स को नहीं हटाया जाना चाहिए, मौजूदा सिविल डिफेंस वॉलन्टियर्स को कंटिन्यू रखिये और जब तक, वो कह रहे थे कि नहीं हम होमगार्ड करेंगे। मैंने कहा ठीक है जब तक होमगार्ड नहीं आते तब तक इनको रख लो और होमगार्ड, इन्हीं को नियुक्त कर दो होमगार्ड।

आपको कानूनी पेंच ही तो फंसाने हैं। ये जो आज सिविल डिफेंस वॉलन्टियर काम कर रहे हैं इनको एक्सपीरियंस है, इनको अनुभव है, कई दिन से काम कर रहे हैं। मैंने कहा इन्हीं को होमगार्ड बना देना। मेरे फाइल के ऊपर नोटिंग है मेरी, आप जो नोटिंग की बात..

माननीय विकास मंत्री (श्री गोपाल राय): सर, ये जो होमगार्ड जो लगे हैं न उनको भी मार्च में हटाने का ऑर्डर दे दिया उन्होंने।

माननीय मुख्यमंत्री: जो अभी लगे हुए हैं,

माननीय विकास मंत्री: जो लगे हुए हैं, मार्च में वो भी हटा दिये जाएंगे जो बचे हुए होमगार्ड हैं।

माननीय मुख्यमंत्री: और अब खुद हटाकर बीजेपी वाले उनके धरने में जाके टेसुए, अपने मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। थोड़ी सी शर्म बची है तुम लोगों के अंदर तो डूब मरो चुल्लू भर पानी के अंदर तुम लोग। इस तरह की गंदी राजनीति करते हों। खुद ही हटवाते हों और खुद ही उनके उसमें, धरने में जाकर तुम रोना रोते हों।

अभी आपने कहा, इनको नियमित किया जाना चाहिए, करने को तैयार हूं मैं, चलो मैं और तुम चलते हैं अभी एल.जी. साहब के पास। अभी आपने कहा हैं, चलो मेरे साथ। अगर माई के लाल हों तो चलो मेरे साथ, अभी एल.जी. साहब के पास चलो, मैं करने को तैयार हूं, मैं जहां साइन कहोगे, खाली कागज पर दस्तखत करने को तैयार हूं, एल. जी. से कराकर लाओ, तुम्हारा एल.जी. हैं, झूठ बोलते हो। जिस फाइल

पर दस्तखत करने, इनकी बहाली के लिए मैं अभी तैयार हूं फाइल पर साइन करने के लिए, इनको नियमित करने के लिए मैं अभी तैयार हूं साइन करने के लिए। नौटंकी मत करो, नौटंकी मत करो, नाटक मत करो, गंदी राजनीति मत करो।

कल मेरे को एक चिट्ठी लिखी एल.जी. साहब ने। मैं इनकी मांग का समर्थन करता हूं, मैंने बार-बार एल.जी. साहब से दो ही बात कही हैं और वो होनी चाहिए, मैं इसका भी समर्थन करता हूं कि एक तो ये जब तक बहाली नहीं होती नए लोगों की इनको जारी रखा जाए और दूसरा ये कि जब तक, जब ये इनकी बहाली होगी तो इन्हीं लोगों को दूसरे होमगार्ड की तरह नियुक्त कर दिया जाए। मैंने एक हफ्ते पहले भी फोन किया एल.जी. साहब, मैंने कहा जो तुमने अब एड निकाला है इस एड में लिखा हुआ है, इस एड में इनको कोई वेटेज नहीं दिया हुआ पुराने वालों को। मैंने कहा सर आपने भी प्रॉमिस किया था, मैंने भी प्रॉमिस किया था कि इनको वेटेज दिया जाएगा, वेटेज क्यूं नहीं दिया, हां-हां, मैं कराता हूं, कराते नहीं हैं फिर। वेटेज क्यूं नहीं दिया जा सकता इनको, अब ये कहां जाएंगे इनकी तो उम्र हो ली, नौकरी लेने के लिए कहां जाएंगे, इनको वेटेज क्यूं नहीं दे सकते उसके अंदर? न इनकी उम्र बची, न इनका कुछ वो बचा, अब कैसे कहां नौकरी लेंगे? इनको वेटेज देने में क्या दिक्कत है, इनके पास, हर एग्जाम में दिया जाता है जो पुराने वाले होते हैं।

अब कल एल.जी. साहब ने मेरे को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी बहुत गंदी है, उसमें भाषा बहुत ही गंदी है। ''आप लोग petty

political games के लिए काम कर रहे हैं, you are passing the buck for your own inefficiency. अपने स्पीकर साहब को बता देना,'' स्पीकर कोई मेरे अंडर में आते हैं? क्या एल.जी. को ये भी नहीं पता कि जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव तीन स्तंभ हैं कांस्टिटयूशन के। क्या उनको ये नहीं पता कि Speaker is an independent constitutional authority, he does not report to the Chief Minister कि अपने स्पीकर साहब को बता देना कि इसमें से एक्सपंज कर दें प्रोसीडिंग्स में से। मैं कुछ नहीं कह सकता स्पीकर साहब को, हमारे सबके माननीय हैं स्पीकर साहब, मुझे, मैं नहीं कह सकता इनको कुछ भी। 'you and your ministers are accusing me, your statements are white lies, this is a typical example of abuse and scoot game which you seem to have mastered. You have made a career out of it.' ये एल.जी. साहब मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं, ये भाषा है, ये भाषा है, ऐसी भाषा लिखनी चाहिए। कितने भी डिफरेंसिस हों हम दोनों के बीच में, जो मर्जी डिरेंस हों, ऐसी भाषा तो एल.जी. साहब को लिखना शोभा नहीं देता, 'while you and your govt. have done nothing substantive for the development of Delhi and its residents in almost all spheres.' तीन बार चुनाव जीते हैं, आप लोगों की जमानतें जब्त हो गई, कुछ कर ही रहे होंगे तभी हुआ है, कुछ कर ही रहे होंगे दिल्लीवालों के लिए, 'you have done nothing for the people of Delhi. In a bid to maintain the sharaad that you have created through repeated lies perpetuated by an incessant publicity campaign' अभी तो बहुत हैं इसमें गंदी-गंदी

गालियां, मैं इसमें नही जाऊंगा, पर मैं ये समझता हूं कि जो भी provocation हो, जो भी कारण हो, हमें अपनी मर्यादा, शब्दों की मर्यादा और भाषा की मर्यादा कभी लांघनी नहीं चाहिए। बातचीत से सभी समाधान निकलते हैं अगर नीयत अच्छी हो तो।

अब मैं ये दिखाता हूं कि ये चल क्या रहा है दिल्ली के अंदर। मैंने इनको फिर कल जवाब भेजा है। जब से सक्सेना साहब एल.जी. बने हैं तब से दिल्ली के अंदर ढेर सारे रेगुलर, रूटिन के काम बंद होते जा रहे हैं, बंद होते जा., एक नहीं, जैसे बस मार्शलों को बंद कर दिया, चलती हुई स्कीम थी। इनके पहले वाले जो एल.जी. थे वो हमें नए काम नहीं करने देते थे, हम कहते थे जी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, वो नहीं लगाने देते थे। हम कहते थे मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, नहीं लगाने देते थे। लेकिन पुराने दिल्ली की जो व्यवस्था चल रही थी पानी की, दवा की, टेस्ट की, उनको नहीं रोका उन्होंने, उन्होंने उनको नहीं रोका। अब जो एल.जी. साहब आए हैं, पिछले दो साल से दिल्ली के अंदर एक जो चल रहा है कि अब दिल्ली के अंदर जो चालू चीजें हैं, सर्विसेज हैं, दिल्ली के लोगों के जो, दिल्ली की लाइफ लाइंस हैं, मूलभूत जरूरतें हैं उनको बंद किया जा रहा है आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए और वो ट्रेंड बन गया। बंद करते हैं, फिर बीजेपी वाले हमारे को गाली देते हैं कि केजरीवाल से चल नहीं रहा, करवाते ये हैं। मैंने कल उनको लिखा। अक्टूबर, 2022 से दिसंबर 2022 के बीच में सारे मोहल्ला क्लिनिक के टेस्ट बंद करवा दिए गए, दवाइयां बंद करवा दी गई, उनके रेंट की पेमेंट बंद करवा दी गई,

बिजली की पेमेंट बंद करवा दी गई, डॉक्टरों की तनख्वाह रोक दी गई, अक्टूबर, 2022 से दिसंबर 2022, एमसीडी चुनाव के जस्ट पहले। क्या कारण था भई, आम आदमी पार्टी के वोट कम करने थे और बीजेपी के वोट बढ़ाने थे। वोटों के लिए तुम किस हद तक गिरोगे बीजेपी वालों। ओपीडी, सिंतबर, 2023 से फरवरी, 2024 के बीच में ओपीडी के काउंटर के ऊपर अस्पतालों के अंदर जो वो डाटा एंट्री ऑपरेटर बैठे थे, एक shot में सबको हटा दिया, अब कोई अस्पताल जाता है तो खिड़कियों पर कोई बैठा हुआ नहीं मिलता। ये सब हमने लड़-लड़ के दुबारा चालू कराए हैं। ये तो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं दिल्लीवालों को मारने की, मरने नहीं दूंगा, मैं जब तक जिंदा हूं तब तक दिल्लीवालों के ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। पिछले सात महीने से दिल्ली जल बोर्ड के फंड, जो इस विधान सभा ने जल बोर्ड के फंड पास किए, आप लोगों ने मान लो कहा 5 हजार करोड़ रुपये जल बोर्ड के लिए पास, वो फंड रोककर बैठा है फाइनेंस डिपार्टमेंट, वो फंड नहीं देने दे रहे एल.जी. साहब जल बोर्ड को। जगह-जगह पूरी दिल्ली के अंदर सीवर की.. बेसिक मेंटनेंस खत्म हो गया है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के लोगों को पानी के लिए, सीवर के लिए तरसाओगे तुम लोग और हम हाई कोर्ट गए इसके खिलाफ। हाई कोर्ट ने एक महीने पहले ऑर्डर किया है फाइनेंस सेक्रेटरी को कि पैसे दो जल बोर्ड के, फिर भी नहीं दे रहे, न, हाई कोर्ट की भी नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, किसी को नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है, पलट देते हैं उसको। अरे किसको मानोगे तुम? देश की जनता को नहीं मानते, दिल्ली

की जनता को नहीं मानते, चुनी हुई सरकार को नहीं मानते, हाई कोर्ट को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, अजीब तानाशाही हो गई तुम्हारी। अब बस मार्शलों को तुमने एक नवंबर से बंद कर दिया। डीटीसी के पेंशनधारी जिनको लगातार हर महीने पेंशन मिलती थी, सात-आठ साल में कभी दिक्कत नहीं हुई हमारी सरकार बनने के बाद, उनकी मई महीने से, मई से पेंशन रोक दी उनको। अब लड़-लड़कर दिलवाई है पेंशन, अभी मिली है पिछले महीने, कई महीनों की पेंशन एक साथ दिलवाई है मैंने, 6 महीने की एक साथ।

'फरिश्ते स्कीम' कि दिल्ली की सीमाओं के अंदर किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसका जहां मर्जी वो इलाज करा ले प्राइवेट में, बड़े से बड़े प्राइवेट, उसका सारा खर्चा हम देते थे। 23 हजार लोगों की हमने जान बचाई है एक्सीडेंट वालों की, एल.जी. साहब ने वो स्कीम भी बंद करा दी। और ये बड़े मजे की बात ये है एल.जी. साहब को मैंने जाकर बताया, पिछले 6 महीने में मेरी जितनी मीटिंग हुई हैं, बार-बार मैंने एल.जी. साहब को कहा है जी मैं अफसरों को बुलाता हूं और मैं उनसे पूछता हूं भई क्यूं बंद कर रहे हों, हर अफसर ये कहता है मेरे को एल.जी. ने बुलाकर धमकाया, मेरे को एल.जी. ने बुलाकर धमकी दी है कि काम अगर करोगे तो, एल.जी. साहब बोले मैंने तो कभी धमकी नहीं दी। मुझे नहीं पता सच्चाई क्या है। अफसर कह रहे हैं एल.जी. ने बुलाकर धमकाया, एल.जी. साहब कह रहे हैं मैंने कोई धमकी नहीं दी। तो ये अचानक पिछले दो साल के अंदर दिल्ली की सारी पेमेंट बंद क्यूं होती जा रही हैं। दवाइयों की पेमेंट बंद हो रही है,

टेस्ट की पेमेंट बंद हो रही है, और मंत्री लिखित में आदेश दिए जा रहे हैं, उनके आदेश नहीं माने जा रहे। ये ही अफसर हैं, अफसर नहीं बदले, सारे के सारे वो ही अफसर हैं जो अभी तक जो अफसर काम कर रहे थे सरकार के लिए अचानक उन अफसरों ने जो बेसिक सर्विसेज हैं वो भी प्रोवाइड करना बंद कर दिया। कुछ तो गड़बड़ है। मैंने कहा चलो जी हम आपकी बात मान लेते हैं कि आप नहीं कर रहें, तो आप इनको सस्पेंड करो फिर, सस्पेंड भी नहीं करेंगे, ट्रांसफर करो, ट्रांसफर भी नहीं करेंगे। तो भई दाल में तो कुछ काला है। सारा देश तो पागल नहीं है और आप ही अकेले सयाने नहीं हों।

अब धीरे–धीरे सबको पता चलने लगा है कि ये चल क्या रहा है दिल्ली के अंदर। तुम लोग किसी भी हद तक गिर सकते हों, इस देश को बेच सकते हो तुम लोग केवल 4 वोट के लिए। मेरी अंत–पंत में बीजेपी वालों से यही निवेदन है कि राजनीति करो लेकिन ऐसी मत करो कि जिसमें इतना पाप करना पड़े। वोट के लिए अच्छे काम करो, पॉजिटिव राजनीति करो, अच्छे काम करो। अच्छे काम करोगे, आपके पास भी, दिल्ली तो मिक्स्ड सा है उसमें बहुत सारे काम आपके हैं, पुलिस आपके पास है, ठीक करो न कानून–व्यवस्था, वो तो करोगे नहीं। डीडीए आपके पास है, मकान बनाओ लोगों के लिए, मकान बना–बनाकर दो उनको, वो तो करोगे नहीं। और इतनी सारी व्यवस्थाए आपके पास हैं, पूरी केंद्र सरकार यहां बैठी है, इतने काम करके दिल्ली के लोगों का दिल जीत सकते हों, वो नहीं करोगे। हमको काम करने से रोकोगे। हमें काम करने दो, लोगों को ये पसंद नहीं आता। आप लोग समझते

हों आप ही चतुर हो, अंत में सबको पता चल जाता है कि ये चल क्या रहा है, बीजेपी वाले कर क्या रहे हैं। एल.जी. को कहकर पहले काम रूकवाते हैं, एल.जी. साहब धमकाते हैं अफसरों को, अफसर फिर काम रोकते हैं और फिर जाकर धरने पर बैठ जाते हैं उनके साथ, फिर मेरी हाय–हाय करते हैं, ये नहीं चलेगा, मत करो, अच्छी बात नहीं है।

माननीय अध्यक्षः अब माननीय सदस्य, दिलीप पांडे जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं वे न कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जी, हाँ पक्ष जीता,

ये संकल्प सर्वसम्मति से पारित हुआ।

अब सदन की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 01 मार्च, 2024 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद। लंच के लिए सभी आमंत्रित हैं, लंच की व्यवस्था है।

(सदन की कार्यवाही दिनांक 01 मार्च, 2024 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा ग्राफिक प्रिंटर्स, 2965 /41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।